

महिला आरक्षण को चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती है सरकार

इस सोच के तहत संसद में तीन दिन का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है, 16 से 18 अप्रैल को

-नेपू मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। संसद के बजट सत्र में एक तीसरा विशेष सत्र देखने को मिलेगा, जिसे 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिनों के लिए बुलाया जाएगा, ताकि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जा सके।

लोकसभा और राज्यसभा को आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्थगित कर दिया गया, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए नहीं।

दोनों सदनों की 16 अप्रैल को फिर से बैठक होगी, जहां सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संशोधित विधेयक पेश करेगी।

महिलाओं को आरक्षण देने की अपनी मंशा का संकेत देने की जल्दबाजी में सरकार इसे परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना से जोड़ना चाहती है, जो अब पुरानी हो चुकी है

■ इस मकसद से सत्र में विशेष संविधान संशोधन विधेयक पेश होगा। हालांकि, अभी सरकार के सांसदों की पर्याप्त संख्या नहीं है, इस संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए, पर फिर भी सरकार इस संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए अड़ी हुई है।

■ सरकार का मानना है कि अगर विधेयक पारित नहीं हुआ तो यह मैसैज तो जाएगा ही, कि सरकार महिला आरक्षण के पूर्णतया पक्ष में है। पर, विपक्ष सरकार के इस प्रयास को सफल नहीं होने दे रहा है।

■ क्योंकि, विपक्ष, इस दौरान विधानसभा चुनाव में व्यस्त होगा। अतः सरकार की सोच है कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करने का पूरा नाटक वह आसानी से रच सकेगी।

और इसका कोई खास औचित्य नहीं माना जा रहा है।

अन्य संशोधन भी प्रस्तावित है,

लेकिन राजनीतिक दल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, यह संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करना आसान नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा के पास पर्याप्त संख्या नहीं है।

भले ही यह पूरा मामला एक राजनीतिक नाटक साबित हो और विधेयक पारित न हो, पर सरकार यह प्रचार जारी रख सकती है कि वह विधेयक पास करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था।

यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है।

इस बीच, विपक्षी दल विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं और भाजपा इससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

महिलाओं के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में तीन दिनों तक खींचतान और राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा।

एसआई भर्ती 2025 में 2021 के अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश

जयपुर, 2 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की एसआई, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े मामले में एसआई भर्ती, 2021 में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को अंतिम राहत दी है। अदालत ने इन्हें अस्थाई तौर पर 5 व 6 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थियों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों के

■ सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की एसआई भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों को राहत दी।

परिणाम तब तक घोषित नहीं किए जाएंगे, जब तक संबंधित हाईकोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता। जस्टिस दीपाकर दत्ता की खंडपीठ ने यह आदेश सूरजमल मीणा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए दिया। अदालत ने संबंधित अभ्यर्थियों को कहा है कि वे अदालती आदेश की कॉपी 4 अप्रैल तक परीक्षा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर जमा कराएं और वहां से अपने एडमिट कार्ड प्राप्त करें।

प्रार्थी पक्ष की ओर से सीनियर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात जजों को नौ घंटे बंधक बनाकर रखा गया बंगाल के मालदा जिले में

ये जुडिशियल अफसर एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट के सत्यापन का कार्य कर रहे थे

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य विधानसभा चुनावों से पहले की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राज्य में अराजकता का माहौल व्याप्त है।

मालदा जिले के मोथाबाड़ी क्षेत्र में एक घटना सामने आई, जिसमें एसआईआर कार्य कर रहे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दर रात केन्द्रीय बलों की एक टुकड़ी ने मौके पर पहुंचकर इन अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं। आरोप है कि ये घटनाएं उसी तरह हो रही हैं, जैसा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों से करने का आ

■ सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का उदाहरण देते हुए टिप्पणी की कि बंगाल में हर चीज का "राजनीतिकरण" हो चुका है। अतः सवाल यह उठ रहा है कि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश में बढ़ती अराजकता व हिंसा के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही।

■ ममता बनर्जी इस मुद्दे पर सार्वजनिक मंच से हिंसा प्रतीपादित कर रही हैं तथा कह रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट के सत्यापन का कार्य पूरा नहीं होने देंगे।

■ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन जुडिशियल अफसरों ने राज्य सरकार को और कोलकाता हाई कोर्ट को पहले ही सूचित कर दिया, अपनी सुरक्षा के बारे में, विशेषकर उस क्षेत्र में जहाँ कि सत्यापन का काम कर रहे थे।

■ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार की भारी भर्त्सना की, इन जुडिशियल अफसरों को पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करने के कारण। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अगर जुडिशियल अफसरों को ही सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती तो निष्पक्ष, निडर, चुनाव होने की संभावना की कल्पना ही व्यर्थ है।

कर रही है। बताया गया कि महिलाओं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आप ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाया

आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह लवली युनिवर्सिटी के चीफ अशोक मित्तल की नियुक्ति की है

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी लाइन का उल्लंघन करने के कारण राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उच्च सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है और उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया है, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक-चेयरमैन हैं।

गुरुवार को आप की ओर से राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा गया, जिसमें पार्टी के उपनेता पद के लिये पंजाब से निर्दिष्ट चुने गए मित्तल का नाम प्रस्तावित किया गया।

मित्तल ने मीडिया से कहा, "हमारी पार्टी में हर किसी को बोलने का समय मिलता है; यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। राघव चड्ढा को भी भविष्य में राज्यसभा में बोलने का अवसर दिया जाएगा।"

आईपैक के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की रेड

बेंगलुरु, 02 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में चोटिंग से पहले एक बार फिर से आईपैक के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की। बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में यह कार्यवाही चल रही है। इससे पहले कोलकाता स्थित ऑफिस में ईडी की रेड हुई थी। छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल

■ आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी का चुनाव प्रबंधन संभाल रही है और यह रेड कोयला तस्करी के मामले में की जा रही है।

की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई थीं। इस दौरान खूब सियासी बवाल हुआ था।

दरअसल, ईडी की यह छापेमारी कोयले की तस्करी को लेकर चल रही है। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में चल रही है। आईपैक पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए चुनाव प्रबंधन का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सचिवालय को पत्र भेजकर मित्तल की नियुक्ति की सूचना दी गई तथा पत्र में राघव चड्ढा को वक्ताओं की सूची से बाहर रखने का आग्रह भी किया गया है।

■ आप नेतृत्व का आरोप है कि राघव काफी समय से पार्टी लाइन फॉलो नहीं कर रहे थे, पार्टी के वॉकआउट के समय भी वे सदन में बैठे रहते थे, यही नहीं उन्होंने पार्टी नेतृत्व से भी दूरी बना ली है।

■ चर्चा है कि राघव भाजपा नेतृत्व के समर्थक में भी हैं। इसलिए आप ने पंजाब से राज्यसभा सांसद और लवली युनिवर्सिटी के संस्थापक चेयरमैन अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बना दिया है।

आप ने राज्यसभा सचिवालय से यह भी अनुरोध किया है कि चड्ढा को वक्ताओं की सूची से बाहर रखा जाए। सूत्रों के अनुसार, 37 वर्षीय चड्ढा पिछले कुछ महीनों में कई बार सदन में

पार्टी लाइन के खिलाफ जाते रहे हैं। 12 मार्च को जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिस पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वृद्धा से 80 लाख की साइबर ठगी करने वाले की अग्रिम जमानत से इंकार

जयपुर, 2 अप्रैल (निर्स)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर की 83 साल की वृद्धा को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 80 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश नवीन टेमानी की ओर से

■ हाई कोर्ट ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जो समझौते से सुलझाया जा सके।

दायर द्वितीय अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसे समझौते से सुलझाया जा सकता है, बल्कि यह एक संगठित अंतरराष्ट्रीय गंभीर अपराध है, अदालत ने कहा कि यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'5037 बीघा में कितनी ज़मीन पर अतिक्रमण है, नक्शा बनाकर पेश करो'

हाई कोर्ट में 5037 बीघा ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाने की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 2 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा जयपुर में अवाप्त की जा रही 5037 बीघा जमीन में से काफी बड़े हिस्से पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में 'पब्लिक अग्रेसर करप्शन' नामक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश पुष्पेन्द्र पाटी और पुनीत कुमार माथुर ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ए.एस.जी.) के आशयन को मद्देनजर रखते हुए आदेश दिये हैं कि राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे कि उक्त

भूखंड में शेष खुले स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं होने दिये जायेंगा। अदालत ने आदेश में आगे कहा कि हाउसिंग बोर्ड व याचिकाकर्ता के वकील पूरे क्षेत्र का विस्तृत मैप बनायें, जिसमें विवादित क्षेत्र और खुले क्षेत्रों को अच्छे से अंकित किया गया हो, ताकि अतिक्रमण होने से रोका जा सके।

■ याचिकाकर्ता, "पब्लिक अग्रेसर करप्शन" ने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि 12 मार्च 2025 को हाई कोर्ट ने आदेश दिये थे कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अवाप्त की जा रही है, 5 हजार बीघा से भी अधिक भूमि पर से गैरकानूनी अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया है, परंतु अदालती आदेशों के बावजूद, इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

■ हाउसिंग बोर्ड ने कहा, कुल अवाप्त 5037 बीघा जमीन पर से 4000 बीघा पर हमारा कब्जा है, शेष 1037 बीघा जमीन पर कुछ जरूरतमंदों ने कब्जा कर रखा है।

अदालत ने इस दस्तावेज को बनाने व अदालत में पेश करने के लिये हाउसिंग बोर्ड व याचिकाकर्ता को समय दिया है और इस मामले की अगली तारीख 1 मई, 2026 तय की है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका यह कहते हुए दायर की गई है कि 12 मार्च 2025

को अदालत ने आदेश दिये थे कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अवाप्त की जा रही 5 हजार बीघा से भी अधिक भूमि पर से गैरकानूनी अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया है, परंतु अदालती आदेशों के बावजूद इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान

एसजी भरत व्यास की ओर से कहा गया है कि 5037 बीघा में से 4000 बीघा जमीन हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त की जा चुकी है और उसका कब्जा है। शेष भूमि पर कई जगह अतिक्रमण हैं, परंतु वह इसलिये हैं कि जयपुर में शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है और बाहर से आये लोगों को शहर में बसाने के लिये गैरकानूनी कॉलोनियां काटी गईं। उन्होंने कहा कि शहरीकरण रोकना अत्यंत ही मुश्किल काम है। हालांकि गैरकानूनी सोसायटी काटने से सुनियोजित विकास नहीं किया जा सकता है, परंतु राज्य सरकारों को शहर के बाहर से आये गरीबों और रोजगार की खोज में आये लोगों की आवश्यकताओं को भी देखना जरूरी है। उन्होंने अदालत को इस तथ्य से इस मुद्दे पर संवेदनशील करना चाहा कि अतिक्रमण हटाने से कई गरीबों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अदालती आदेश के बावजूद चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ाने पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये

■ याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पूनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 439 चुनावी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिये थे कि 15 फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी स्वायत्तशासी निकायों के चुनाव आयोजित करा दिये जायें।

■ परंतु अदालती आदेशों के बावजूद मुख्य निर्वाचन आयोग ने 20 फरवरी, 2026 को आदेश जारी करे, जिसके तहत मतदाता सूची 22 अप्रैल तक तय की जायेगी और फिर उसका अंतिम प्रकाशन होगा और चुनाव उसके बाद ही हो सकेगा।

अदालत ने इसकी न तो कोई अनुमति दी है, और न ही अदालत से अनुमति मांगी गई है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी पैरवी

के लिये प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि 14 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 439 चुनावी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिये थे कि 15 फरवरी

2026 तक प्रदेश के सभी निकायों के चुनाव आयोजित करा दिये जायें। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिये थे कि परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी

कर ली जाये। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि चुनाव आयोजित नहीं कराने की वजह से कई निकाय गैरकानूनी तरीके से अपने कार्यकाल से डेढ़ से दो वर्ष अधिक से कार्यरत हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं आयोजित होने की वजह से आम जनता के वोट डालने के संविधानिक हक को छीना जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने आदेश दिये थे कि 15 फरवरी तक चुनाव करा दिये जायें।

पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि अदालती आदेशों के बावजूद, निर्वाचन आयोग ने 20 फरवरी, 2026 को आदेश जारी किये, जिनके तहत मतदाता सूची 22 अप्रैल तक तय की जायेगी और उसका अंतिम प्रकाशन हो जायेगा। उन्होंने अदालत को कहा कि ऐसी स्थिति में 15 अप्रैल तक चुनाव आयोजित कराने के आदेश की पालना असंभव है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और टिप्पणी की कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आईआरजीसी कमांडर फतह अलीजादेह की मौत

तेहरान, 02 अप्रैल। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच ईरान को एक और झटका लगा है। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड फोर्स (आईआरजीसी) की बेहद खतरनाक मानी जाने वाली फतेहिन स्पेशल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली फतह

■ ईरानी मीडिया के मुताबिक, फतह अलीजादेह की मौत बुधवार को तेहरान में जारी अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के दौरान हुई।

अलीजादेह की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक, फतह अलीजादेह की मौत बुधवार को तेहरान में जारी अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के दौरान हुई। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

स्वयं को बदल दो, भाग्य बदल जायेगा -कहावत

एक जिला एक उत्पाद नीति राजस्थान : लोकल टू ग्लोबल

राजस्थान की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। यह नीति स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को वैश्विक पटल पर चमकाने का माध्यम बन गई है। राजस्थान सरकार ने इस नीति को अपनाते हुए रेगिस्तानी राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को आर्थिक शक्ति में बदलने का संकल्प लिया है। लोकल टू ग्लोबल का मंत्र यहां साकार हो रहा है, जहां जिले के पारंपरिक उत्पाद न केवल स्थानीय बाजारों में मजबूत हो रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। राजस्थान, जो अपनी रंगीन संस्कृति, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है, इस नीति के माध्यम से आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में शुरू की गई ODOP योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्टता को पहचानना और उसे बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार ने इसे तुरंत अपनाया और 2021 से राज्य स्तर पर इसे लागू किया। राजस्थान सरकार ने इसे प्राथमिकता दी। राज्य में 33 जिलों में से प्रत्येक के लिए एक प्रमुख उत्पाद चुना गया, जो स्थानीय संसाधनों, परंपराओं और बाजार क्षमति पर आधारित है। उदाहरणस्वरूप, बाड़मेर का लेहरीया मिठ, जोधपुर का मोतीकारी कढ़ाई, जयपुर का हस्तशिल्प, उदयपुर का मिनिएचर पेंटिंग और अलवर का मोर पंख शिल्प इनकी बानगी भर है। ये उत्पाद न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान हैं, बल्कि रोजगार सृजन के स्रोत भी बन रहे हैं।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP दृष्टांत स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनों खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकसूत्र छवि प्रस्तुत करता है।

ODOP के तहत राजस्थान के जिलों ने अपनी विशिष्टताओं को निभाया है। बाड़मेर में लेहरीया और बंधेज साड़ियां अब दुबई और अमेरिका के बाजारों तक पहुंच रही हैं। यहां 500 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे उनका उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा। जोधपुर का ब्लू सिटी अब मोतीकारी फनीचर के लिए जाना जाता है। सरकार ने यहां ODOP क्लस्टर विकसित किया, जहां डिजाइन वर्कशॉप आयोजित होते हैं। जयपुर का ब्लू पॉन्टी और कोमती पत्थर उद्योग को बढ़ावा मिला। अलवर के हस्तशिल्प और दौसा के आंबला उत्पाद न केवल खेती को प्रोत्साहित किया। कोटा का कोटा स्टोन और बांसवाड़ा का बांस उत्पाद भी चमक रहे हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे स्थानीय संसाधन वैश्विक अवसर बन रहे हैं।

यह नीति स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को वैश्विक पटल पर चमकाने का माध्यम बन गई है। राजस्थान सरकार ने इस नीति को अपनाते हुए रेगिस्तानी राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को आर्थिक शक्ति में बदलने का संकल्प लिया है। लोकल टू ग्लोबल का मंत्र यहां साकार हो रहा है, जहां जिले के पारंपरिक उत्पाद न केवल स्थानीय बाजारों में मजबूत हो रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। राजस्थान, जो अपनी रंगीन संस्कृति, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है, इस नीति के माध्यम से आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP दृष्टांत स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनों खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकसूत्र छवि प्रस्तुत करता है।

ODOP के तहत राजस्थान के जिलों ने अपनी विशिष्टताओं को निभाया है। बाड़मेर में लेहरीया और बंधेज साड़ियां अब दुबई और अमेरिका के बाजारों तक पहुंच रही हैं। यहां 500 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे उनका उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा। जोधपुर का ब्लू सिटी अब मोतीकारी फनीचर के लिए जाना जाता है। सरकार ने यहां ODOP क्लस्टर विकसित किया, जहां डिजाइन वर्कशॉप आयोजित होते हैं। जयपुर का ब्लू पॉन्टी और कोमती पत्थर उद्योग को बढ़ावा मिला। अलवर के हस्तशिल्प और दौसा के आंबला उत्पाद न केवल खेती को प्रोत्साहित किया। कोटा का कोटा स्टोन और बांसवाड़ा का बांस उत्पाद भी चमक रहे हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे स्थानीय संसाधन वैश्विक अवसर बन रहे हैं।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP दृष्टांत स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनों खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकसूत्र छवि प्रस्तुत करता है।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP दृष्टांत स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनों खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकसूत्र छवि प्रस्तुत करता है।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP दृष्टांत स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनों खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकसूत्र छवि प्रस्तुत करता है।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP दृष्टांत स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनों खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकसूत्र छवि प्रस्तुत करता है।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP दृष्टांत स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनों खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकसूत्र छवि प्रस्तुत करता है।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP दृष्टांत स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनों खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकसूत्र छवि प्रस्तुत करता है।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP दृष्टांत स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनों खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकसूत्र छवि प्रस्तुत करता है।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP दृष्टांत स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनों खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकसूत्र छवि प्रस्तुत करता है।

दिन में बिजली और सौर ऊर्जा क्रांति से सशक्त होता किसान



पुष्पेंद्र सिंह राणावत

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों में वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का महत्वाकांक्षी संकल्प लेकर इसे तेजी से क्रियान्वित करवा रहे हैं। दौसा एवं करौली जिले के कृषि उपभोक्ताओं को खेती के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली सुलभ करने के साथ ही अब कुल 24 जिलों के कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली सुलभ कराया जा रहा है।

अब जयपुर डिस्कॉम के 9 जिलों- धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डींग, दौसा, करौली एवं भरतपुर जिलों में दिन में बिजली मिलने से किसान सुरक्षित वातावरण में, बेहतर निगरानी के साथ अपनी फसल की सिंचाई कर सकते हैं। दिन में बिजली उपलब्ध कराए जाने वाले जिलों में हो रहे निरंतर विस्तार से स्पष्ट है कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे राज्य में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2027 तक सभी जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

चित्तौड़गढ़ एवं डूंगरपुर तथा जोधपुर डिस्कॉम के 3 जिलों-जालौर, सिराही एवं पाली में भी कृषकों को दिन के दो ब्लॉक में आपूर्ति की जा रही है।

जयपुर डिस्कॉम ने विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए दौसा जिले में 33 केवी के 18 तथा करौली जिले में 33 केवी के 6 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए हैं। इसके साथ ही दौसा में 33 केवी के 47 सब स्टेशनों पर ट्रांसफार्मरों में 128.95 एमपीवी की क्षमता वृद्धि की गई है। करौली में 33 केवी के 15 सब स्टेशनों पर 49.45 एमपीवी की क्षमता बढ़ाई गई है। दोनों जिलों में पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी में 32 मेगावाट क्षमता के 17 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। दौसा जिले के 52,460 तथा करौली जिले के 35,341 कृषि उपभोक्ता अब दिन में बिजली आपूर्ति का उपभोग कर सकते हैं।

कृषकों को इन जिलों में कड़ाके की सर्दी एवं बारिश में रात्रि के समय सिंचाई करने की मजबूरी नहीं रहेगी। इन 24 जिलों में दिन में बिजली मिलने से किसान सुरक्षित वातावरण में, बेहतर निगरानी के साथ अपनी फसल की सिंचाई कर सकते हैं। दिन में बिजली उपलब्ध कराए जाने वाले जिलों में हो रहे निरंतर विस्तार से स्पष्ट है कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे राज्य में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2027 तक सभी जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इस परिवर्तन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मजबूत किए गए विद्युत ढांचे की है। नए ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना, ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि और वितरण नेटवर्क के विस्तार ने इस योजना को व्यवहारिक रूप दिया है। राज्य सरकार ने नीति बनाकर इसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना भी तैयार की है। इस पूरी पहल का सबसे सशक्त आधार केवल पारंपरिक बिजली आपूर्ति नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा के रूप में उभरती नई शक्ति है। पीएम-कुसुम योजना में इस बदलाव को गति दी है और राजस्थान को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। राज्य में अब तक लगभग 1961 मेगावाट क्षमता के 940 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इनमें से अधिकांश पिछले दो वर्षों में ही पूरे हुए हैं। राजस्थान ने अब सूर्य की ऊर्जा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। कुसुम योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने किसान की भूमिका को पूरी तरह बदल दिया है। किसान केवल बिजली का उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि वह ऊर्जा उत्पादक भी बन गया है। खेतों में लागू सौर पंपों के माध्यम से किसान दिन में सिंचाई कर रहा है, डीजल पर उसकी निर्भरता समाप्त हो रही है और उत्पादन लागत कम हो रही है। अतिरिक्त बिजली को दिन में बेचकर किसान आय का एक नया स्रोत भी प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार, अनदाता अब ऊर्जादाता के रूप

में भी उभर रहा है। इस परिवर्तन का राज्य की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संरचना पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न बिजली सीधे स्थानीय ग्रिड से जुड़ने के कारण ट्रांसमिशन लॉस में कमी आई है और बिजली वितरण अधिक प्रभावी हुआ है। लगभग 90 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ राजस्थान का ऊर्जा क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। महंगे थर्मल पावर पर निर्भरता घट रही है और स्वच्छ ऊर्जा का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है, जल संसाधनों पर दबाव कम हो रहा है और वायु प्रदूषण घट रहा है। यह योजना केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी सशक्त माध्यम है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में भी इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सोलर संयंत्रों की स्थापना, संचालन और रखरखाव ने नए रोजगार अवसर पैदा किए हैं। युवाओं को तकनीकी क्षेत्रों में काम करने के अवसर मिल रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई गतिशीलता आई है। अब खेती फसल उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन के साथ बहुआयामी गतिविधि बन चुकी है।

राज्य सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी कई नवाचार किए हैं। सौर

संयंत्रों की स्वीकृति, ऑनलाइन एपीएम, मोटर टेंस्टिंग और ग्रिड कनेक्टिविटी जैसी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाया गया है। वन-स्टॉप समाधान प्रणाली ने किसानों और निवेशकों के बीच विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाया है। इससे परियोजनाएँ तेजी से धरातल पर उतर रही हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सामान गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति, तकनीकी रखरखाव, किसानों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण और सौर परियोजनाओं के विस्तार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो राजस्थान में दिन में बिजली आपूर्ति और पीएम-कुसुम योजना के समन्वय का मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी नवाचार के बेहतर समन्वय से राजस्थान अब प्रगति के नये सौचन अर्जित कर रहा है। अब राजस्थान का किसान अंधेरे में संघर्ष करने वाला नहीं, बल्कि उजले में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किसान बन रहा है। खेतों में फसल के साथ ही ऊर्जा भी उगा रही है और यही एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राजस्थान की पहचान है।

-पुष्पेंद्र सिंह राणावत, विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री

सरकारी भर्ती में कट ऑफ से आगे की कहानी : जहां प्रतिभा हारती है और सिस्टम चूकता है



सुनील दत्त गोयल

भारत में सरकारी नौकरी केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थायित्व का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। यही कारणा है कि हर वर्ष लाखों युवा अपनी उम्र के सबसे उत्पादक वर्ष इस तैयारी में लग देते हैं - कोचिंग, किराया, किताबें, परिभाषा शुल्क और सबसे बढ़कर मानसिक दबाव - इन सबका बोझ उठाते हुए यह केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन का एक लंबा संघर्ष बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष अंततः न्यायपूर्ण अवसर में बदलता है, या फिर एक ऐसी प्रणाली में फँस जाता है जहाँ प्रतिभा हारती है और सिस्टम चूक जाता है?

आज की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि सरकारी भर्ती प्रणाली धीरे-धीरे एंटी सिस्टम बनती जा रही है। न गति करियर सिस्टम न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं होने के बावजूद, चपरासी, क्लर्क और लोअर ग्रेड की नौकरियों के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएसए और एमबीबी जैसे उच्च शिक्षित उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक विस्कृत रोजगार संरचना का संकेत है। इन उम्मीदवारों का उद्देश्य उस पद पर स्थायी रूप से कार्य करना नहीं होता, बल्कि किसी भी तरह सरकारी तंत्र में प्रवेश होना होता है, ताकि आगे चलकर वे बेहतर पदों के लिए प्रयास कर सकें। यहाँ से शुरू होती है वह समस्या, जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला

कर रही है - जाईन-टैन-छोड़ संस्कृति। एक अभ्यर्थी पहले एक पद ग्रहण करता है, फिर कुछ महीनों या वर्षों में दूसरे, अधिक आकर्षक पद पर चयनित होकर उसे छोड़ देता है। यह अब अपवाद नहीं, बल्कि एक स्थापित प्रवृत्ति बन चुकी है। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा कई पदों पर चयन और त्याग होता है, जिससे कई पिछली सीटें अनावश्यक रूप से खाली हो जाती हैं।

ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोगों का सपना सिर्फ आईएसएस बनने का होता है, लेकिन उनका सिलेक्शन आईपीएस, आईआरएस या अन्य अमीनस्थ सेवाओं में होता है, तो वो उसको भी स्वाइन कर लेते हैं और बाद में वह बार-बार आईएसएस की परीक्षा देते रहते हैं और जब अंत में उनका आईएसएस में सिलेक्शन हो जाता है तो अपनी तमना पूरी होने पर वो पिछला पद छोड़ देते हैं। इनके इस क्रम को वजह से पिछली दो तीन सीटें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग रोजगार से वंचित रह जाते हैं, कायदे में जिनको वह पुरानी सीट मिलनी चाहिए थी। यदि हम आधिकारिक अंकों को देखें, तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। संसद में प्रस्तुत हालिया आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में लगभग 9.6 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। कुछ स्वतंत्र विश्लेषणों में यह संख्या 10 लाख के आसपास भी बताई गई है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और न्यौक्ति सिस्टम जैसे अनुभव बताते हैं कि 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक चयनित उम्मीदवार अंतिम रूप से सेवा में नहीं टिकते - या तो वे जाईन नहीं करते या जाईन करने के बाद जल्द ही सेवा छोड़ देते हैं। राज्यों की स्थिति इससे भी अधिक असंतुलित है। उत्तर प्रदेश में लगभग 5.5 लाख पद, राजस्थान में 1.5 से 2 लाख पद, और बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में भी लाखों पद लंबे समय तक रिक्त रहते हैं। यह केवल

भर्ती में देरी नहीं, बल्कि पोस्ट-सेलेक्शन अस्थिरता का स्पष्ट संकेत है। जब कोई उम्मीदवार चयनित होता है, तो सरकार उस पर प्रशिक्षण, वेतन, आवास और अन्य सुविधाओं के रूप में लाखों रुपये खर्च करती है। कई मामलों में यह खर्च प्रति उम्मीदवार 2 से 10 लाख रुपये या उससे अधिक होता है। उच्च सेवाओं में यह लागत और भी अधिक होती है। यह पैसा करदाताओं का होता है। लेकिन जब वही उम्मीदवार कुछ समय बाद सेवा छोड़ देता है, तो यह पुराने निवेश संकलनात्मक बन जाता है - जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता।

इससे भी बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब वह सीट खाली रह जाती है और उसी भर्ती को प्रतीक्षा सूची को सक्रिय नहीं किया जाता। यह स्थिति डेड सीट कहलाती है - जहाँ पद मौजूद है, जब्त पीछे है, जरूरत मौजूद है, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा। जिला स्तर पर इसका अर्थ बेहद गंभीर होता है - स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, प्रशासन में अधिकारी नहीं - और इसका सीधा नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता है। यहाँ लास्ट कट-ऑफ की अवधारणा पूरी तरह सवालियों के घेरे में आ जाती है। कट-ऑफ एक तकनीकी सीमा है, लेकिन जब चयनित उम्मीदवार सेवा में नहीं टिकते और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलता, तो यह कट-ऑफ न्याय नहीं, बल्कि अन्याय का उपकरण बन जाती है। जो उम्मीदवार केवल कुछ अंकों से पीछे रह गए थे, वे केवल इसलिए बाहर रह जाते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें अग्रसर देने में विफल रहता है। यह न केवल प्रतिभा का नुकसान है, बल्कि सिस्टम की नैतिक विफलता भी है। इस पूरी समस्या को यदि कार बिंदुओं में समझें, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है -

- (1) एक ही व्यक्ति द्वारा कई पदों पर चयन और त्याग
- (2) सरकारी संसाधनों - वेतन, प्रशिक्षण, सपना - का दुरुपयोग
- (3) प्रतीक्षा सूची के योग्य

उम्मीदवारों को अवसर न मिलना

(4) चयन प्रक्रिया में देरी और रिक्त पदों की बढ़ती संख्या

अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? और क्या केवल सुधार से काम चलेगा या एक कठोर नीति की आवश्यकता है? सबसे पहला और सबसे प्रभावी समाधान है - रोलिंग वेटलिस्ट प्रणाली का अनिवार्य क्रियान्वयन। इसका सिद्धांत बेहद सरल है - जिस भर्ती वर्ष की सीट खाली होती है, उसे उसी वर्ष की प्रतीक्षा सूची से 12-18 महीने के भीतर भर दिया जाए। यह कोई जटिल सुधार नहीं है, बल्कि एक बुनियादी प्रशासनिक जिम्मेदारी है, जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया है। यदि यह प्रणाली लागू होती है, तो डेड सीट की समस्या लगभग समाप्त हो सकती है और अंतिम कट-ऑफ से थोड़ा पीछे रह गए उम्मीदवारों को वास्तविक न्याय मिल सकता है। लेकिन केवल रोलिंग वेटलिस्ट पर्याप्त नहीं है। अब समय आ गया है कि सरकार एक कठोर और स्पष्ट नीति ढांचा तैयार करे। उदाहरण के लिए - जब कोई अभ्यर्थी पहली बार किसी सरकारी पद के लिए आवेदन करे, तो वह यह लिखित घोषणा दे कि वह उसी पद के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा।

इसके साथ ही न्यूनतम सेवा बांड (3-5 वर्ष) लागू किया जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार से अवधि से पहले सेवा छोड़ता है, तो उससे प्रशिक्षण और अन्य खर्चों की वसूली की जाए। इसी तरह, क्रॉस-सर्विस परीक्षाओं के लिए सीमित प्रयास और कूल-ऑफ अवधि भी तय की जानी चाहिए, ताकि उम्मीदवार बिना जिम्मेदारी के बार-बार सिस्टम का उपयोग न कर सकें। नीति-निर्माण के स्तर पर पारदर्शिता भी अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न विभागों में डेटा बिखरा हुआ है - कितने पद भरे गए, कितने उम्मीदवारों ने जाईन नहीं किया, कितनों ने सेवा छोड़ी, कितनी सीटें खाली रह गईं - इन सभी का समन्वित और नियमित प्रकाशन नहीं होता। यदि यह डेटा सार्वजनिक रूप से

उपलब्ध हो, तो न केवल समस्या का सही आकलन हो सकेगा, बल्कि नीति-निर्माण भी अधिक डेटा-आधारित और प्रभावी होगा। इस पूरे मुद्दे का एक महत्वपूर्ण नैतिक आयाम भी है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या यह उचित है कि कोई व्यक्ति अपने करियर के लिए बार-बार अवसर ले और फिर छोड़ दे, जबकि कोई दूसरा योग्य उम्मीदवार उसी अवसर के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा हो? यह न केवल संसाधनों को बर्बाद है, बल्कि उन उम्मीदवारों के साथ भी अन्याय है, जिन्हें लिए वह नौकरी अंतिम लक्ष्य है। यदि कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, तो उसे सीधे उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए, न कि अन्य पदों को बैकअप प्लान के रूप में उपयोग करना चाहिए। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नीति और नैतिकता दोनों की विफलता है। यदि इसे समय रहते नहीं सुधारा गया, तो यह न केवल प्रशासनिक क्षमता को कमजोर करेगा, बल्कि युवाओं के बीच सिस्टम के प्रति विश्वास को भी खत्म कर देगा। आज सरकार, भर्ती एंजिनीयर्स और नीति-निर्माताओं के सामने एक सीधा प्रश्न खड़ा है - क्या वे एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, जहाँ सीटें खाली रहें, संसाधन बर्बाद हों और योग्य उम्मीदवार बाहर रह जाएँ? या वे एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहते हैं, जहाँ हर सीट भरे, हर अवसर का सही उपयोग हो और हर योग्य व्यक्ति को उसका अधिकार मिले?

रोलिंग वेटलिस्ट + न्यूनतम सेवा प्रतिबद्धता + कूल-ऑफ नीति + पारदर्शी डेटा सिस्टम

अब आवश्यकता केवल इच्छाशक्ति की है। क्योंकि जब तक नीति नहीं बदलेगी, तब तक कट-ऑफ के उस पार खड़े लाखों युवाओं के लिए न्याय केवल एक सपना ही बना रहेगा।

-सुनील दत्त गोयल, महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

अटल निश्चय से उपजे विराट संकल्प की बदौलत प्रगति के विकास पथ पर सवार राजस्थान



रामसिंह

विकसित भारत 2047 के गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए पीएमजीएसवाई महत्वपूर्ण बिन्दु भी है, साधन भी है। इस राज्य के क्रियान्वयन से पूर्व राज्य के हजारों गांवों में हर मानसून में जन जीवन ठहर सा जाता था। पुराने और जर्जर पुल बाढ़ के पानी में डूब जाते थे, जिससे असीमित विद्यार्थी और किसान अस्पतालों, स्कूलों और बाजारों जैसी सुविधाओं से कट जाते थे। इसी जरूरत को समझते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में भारत के असंबद्ध

गांवों को सड़क से जोड़ने की मजबूत रणनीति सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक एवं मरुस्थलीय तथा आदिवासी क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी को बसावटों की सर्वांगिक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा आगे चलकर इसमें प्रमुख ग्रामीण सड़कों का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना है। इसी लक्ष्य की शक्ति में राजस्थान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारागत 25 वर्षों में प्रदेश में 75 हजार किमी. सड़कों का निर्माण किया गया एवं 15983 बसावटों/गांवों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया। प्रथम चरण में प्रदेश में लगभग 12086 करोड़ रुपये की लागत से 49 हजार 730 किमी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण कर 15 हजार 983 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया। इसके साथ ही 14043 किमी. सड़कों का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य

किया गया तथा 26 पुलों का निर्माण करवाया गया। जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, चयनित थू रूट्स और ग्रामीण सड़क नेटवर्क को अधिक मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई। योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में करोड़ रुपये की लागत से 3 हजार 468 किमी. लम्बाई की 401 सड़कों का चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया गया तथा 6 पुलों का निर्माण करवाया गया। योजना के तीसरे चरण में भी मौजूदा मार्गों व ग्रामीण सड़कों को उन्नत किया गया ताकि बसावटों से कृषि किसानों, कलेजों, अस्पतालों, अन्य किसान संबंधित उद्यमों तक सुगम एवं त्वरित संबंधित उद्यमों की जा सकें। इस चरण में अब तक प्रदेश में 4 हजार 113 करोड़ रुपये की लागत से 8 हजार 584 किमी. की 912 सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाया गया तथा 36 करवाया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति में है। पीएम जनम - इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के

लिए पीएम-जनम योजना का शुभारम्भ किया गया। प्रदेश में इस योजना के तहत बारां जिले की शाहवाव व किशनगंज ब्लॉक की सहरिया जनजाति बहुल 100 से अधिक आबादी की 31 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई। इसके तहत लगभग 33.48 करोड़ की लागत से 35 किमी. सड़क निर्माण कर 13 बसावटों को सड़क से जोड़ने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है। चौथे चरण में प्रवेश-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चरण प्रदेश में पू

रामचरितमानस पाठ का समापन

भीलवाड़ा। श्री महावीर हनुमान सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 30 घंटे अखण्ड श्री रामचरितमानस पाठ का आज श्रद्धा और उल्लास के साथ समापन हुआ। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ कमाया।

भक्तिमय वातावरण और पूर्णाहुति : कार्यक्रम का शुभारंभ कल विधि-विधान से पूजन और हनुमान जी के आान के साथ हुआ था। 30 घंटे तक चले इस अखंड पाठ के दौरान पूरा क्षेत्र राम नाम के जयकारों से गुंज उठा। आज दोपहर हवन और आरती के साथ पाठ की पूर्णाहुति की गई, जिसमें भक्तों ने सुबह-समूहिक की कामना के साथ आहुतियां दीं।

विशाल प्रसादी वितरण : पाठ के समापन के उपरंत संस्थान द्वारा विशाल प्रसादी (भंडार) का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में उमड़े सैकड़ों

श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर प्रभु का प्रसाद टाहण किया। संस्थान के प्रचार मंत्री कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव पर हर वर्ष इस तरह के आयोजन किए जाते हैं ताकि समाज में सेवा और भक्ति का संदेश जा सके। प्रमुख उपस्थिति : इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र मूंदड़ा संरक्षक धनराज जाजू , संजय झंवर, राजेश सिंहाण, परमेश्वर शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा, बालकिशन पाराशर,श्रवण शर्मा, राजेश शर्मा, मुकेश अठावाल, संजय निर्मल, छोटू सिंह भाटी, युवराज, धर्मवीर पुनिया, हरीश गंधर्व, दीपक शर्मा, कमलेश जागेटिया,राम पहलदा शर्मा.पंकज अठावाल, राजू शर्मा, तुलसीराम माली, नवीन झंवर, दीपक माहेश्वरी, नवीन खण्डेलवाल, जयंत शर्मा, ब्रह्मरानन्द वैष्णव और सुनील कोठारी, आनंदी राम, अनिल पटवारी,सहित संस्थान के अनेक सदस्यों ने सक्रिय सहयोग दिया।

हनुमान जन्मोत्सव पर गुंजे जय श्रीराम के जयकारे

अजमेर, (कासं)। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर गुरुवार को अजमेर शहर सहित पूरे जिले में श्रद्धा, आस्था और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। संकट मोचन हनुमानजी के जन्मोत्सव को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा शहर 'जय श्रीराम' व 'बजरंगबली की जय' के जयकारों से गुंज उठा।

शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों, बजरंगगढ़ बालाजी, घाटी वाले बालाजी, नया बाजार तथा आगरा गेट तिहाड़ मंदिरों में तड़के से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

मंदिरों में दिनभर भजन-कीर्तन, सुंदरकांड पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिससे वातावरण पूरी तरह भाक्तिमय बना रहा। दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव के विशेष अवसर पर महाआरती की गई, जिसके बाद हनुमानजी के जन्मोत्सव को प्रतीकात्मक रूप से केक काटकर मनाया गया। इस

■ विशेष श्रृंगार, सुंदरकांड पाठ और छप्पन भोग की झांकियों से सजा धार्मिक माहौल

दौरान छप्पन भोग की आकर्षक झांकियां सजाई गईं, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।

मराठा कालीन श्री पंचमुखी हनुमान एवं श्री वैभव महालक्ष्मी मंदिर, शिव सागर आगरा गेट में भी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किए गए। यहां प्रातः 5:३0 बजे मंगला आरती के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इसके बाद विशेष पूजा-अभिषेक, दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव महाआरती, प्रसाद वितरण और फूल बंगला झांकी सजाकर भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। पूरे दिन मंदिरों में भक्ति रस की धारा बहती रही और श्रद्धालु भजनों के माध्यम से भगवान श्रीराम और हनुमान जी को रिझाते नजर आए।

कृष्ण नीति दर्शन का भव्य शुभारम्भ

व्यावर (निसं) श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित ज्ञान से जीवन दिशा में सेवा, कृष्ण - नीति दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय संत श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज के सानिध्य में श्री सोमेट परिसर स्थित श्री रंगमंच पर कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ राष्ट्रीय संत श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज के मुखारविंद से हुआ। इस अवसर पर श्री सोमेट परिवार के बेणुगोपाल बांगड - मानद चेयरमैन, हरि मोहन बांगड - चेयरमैन उनकी धर्मपत्नी राजकमल बांगड, प्रशांत बांगड - वासुदेव चेयरमैन उनकी धर्मपत्नी रानी बांगड, विराज बांगड, विदूष बांगड व नीरज अखौरी - प्रबंध निदेशक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री

■ समारोह मुख्य सानिध्य में संपन्न हुआ

गोविंद देव गिरी जी महाराज का श्री परिवार के वरिष्ठ सदस्य बेणुगोपाल बांगड द्वारा माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन किया गया।

श्री परिवार से हरिमोहन बांगड द्वारा श्री स्वामी जी का परिचय श्रद्धालुओं को करवाया गया, उन्होंने बताया कि श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज की शिक्षाओं व व्यवहार को अपने व्यक्तितगत जीवन में उतारकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उन्होंने मंच पर विराजमान आध्यात्मिक, धर्म - भक्ति एवं

अजमेर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रचा सफलता का नया कीर्तिमान

■ माल लदान, समयपालनता और रेल राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

अजमेर, (कासं)।उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने मंडल कार्यालय के 'संवेग' सभाकक्ष में आयोजित प्रेस बार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीता वित्तीय वर्ष बुनियादी ढांचे के विस्तार, यात्री सुविधाओं में सुधार, माल परिवहन, समयपालनता और राजस्व सृजन के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है।

मंडल ने इस अवधि में 1,976.04 करोड़ रुपये की कुल सकल आय अर्जित कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि मंडल के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड मानी जा रही है।

समयपालनता के क्षेत्र में भी अजमेर मंडल ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखी है। पूरे भारतीय रेल नेटवर्क में मंडल ने प्रथम स्थान हासिल करते हुए

97.75 प्रतिशत की समग्र समयपालनता दर्ज की। इसमें मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालनता 97.80 प्रतिशत तथा यात्री ट्रेनों की 98.03 प्रतिशत रही। माल लदान के क्षेत्र में भी मंडल ने नया इतिहास रचा है। वर्ष 2002 में स्थापना के बाद पहली बार अजमेर मंडल ने 10.29 मिलियन टन माल लदान का आंकड़ा पार किया, जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक लदान है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य जारी है, जिनमें से अधिकांश परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए इन स्टेशनों पर

विद्यालय ने 99.07 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया। जाइवी ने 97.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि सानिया ने 96.71 प्रतिशत के साथ द्वितीय स्थान और संजना पनारानी ने 88.50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया।

■ 17 मार्गों व 36 प्रोत्साहन पुरस्कार

कला संकाय से 11 छात्रों को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि 46 छात्रों प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुईं। विज्ञान संकाय से 25 छात्राओं को यह पुरस्कार मिला और 42 छात्राएँ प्रथम श्रेणी में पास हुईं। वहीं कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम भी अत्यंत उत्कृष्ट रहा, जहाँ

व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को दिशा में भी मंडल ने विशेष पहल की है। ऊर्जा बचत के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं तथा स्टेशनों पर शून्य अपशिष्ट नीति को लागू कर स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा दिया गया है। 'रेल मदद' सेवा के तहत अजमेर मंडल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बेहतर प्रतिक्रिया (76.12 प्रतिशत) के मामले में भारतीय रेलवे में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं असंतोषजनक प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखने में भी मंडल शीर्ष तीन में रहा है। शिकायतों के निपटान का औसत समय 17 मिनट दर्ज किया गया, जो उत्तर पश्चिम रेलवे में सबसे कम है। राजू भूतड़ा ने इस सफलता का श्रेय मंडल के सभी रेलकर्मीयों की मेहनत और यात्रियों के सहयोग को दिया। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में 'सुरक्षा पहले, यात्री पहले' के संकल्प के साथ अजमेर मंडल

और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। अजमेर में बन रहे ओवरब्रिज व अंडरपास के कार्यों में देरी के सवाल पर डीआरएम भूतड़ा ने कहा कि गुलाबवाड़ी फाटक अंडरपास दिसम्बर 2026 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है, उन्होंने कहा कि सुभाषनगर व डेयरी फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज के सवाल पर उन्होंने कहा कि उक्त कार्य राज्य सरकार की एजेंसी आरएसआरडीसी व अन्य एजेंसियों द्वारा इन सभी कामों पर निर्माण विभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही है और ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में आने वाली समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान भी किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर मंडल रेलवे प्रबंधक विकास बूरा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रेम रंजन टाकुर, वरिष्ठ संहल वाणिज्य प्रबंधक निहिर देव सिंहल अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

अद्वैत सेंटर के बच्चों ने मित्तल मॉल में लिया आनंद

अजमेर, (कासं)। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर अद्वैत सेंटर के बच्चों को अजमेर स्थित एक संवेदनशील एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समावेशन, समझ और

सामाजिक सहभागिता का संस्कृत संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सेंटर के बच्चों को अजमेर स्थित मित्तल मॉल ले जाया गया, जहाँ उनके लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया गया।

कार्यालय नगर परिषद, व्यावर
क्रमांक-69/2025-26/14188 आम सचुना दिनांक-30.03.26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विष्णु प्रकाश कुमावत पुत्र श्री हरि राम निवासी लक्ष्मी विला चांग गेट व्यावर ने 69 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नगर परिषद व्यावर की सीमा में स्थित जायदाद म्पु. नं. 41, मकान नं. 44(1) कुशल नगर, कॉलेज मार्ग, व्यावर क्षेत्रफल 174.42 वर्गमीटर का मिश्रित पट्टा लेने बाबत आवेदन किया है।
अतः उपरोक्त को वाणिज्यिक पट्टा विलेख जारी किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो मय साध्य के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर आपत्ति अपोहरस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। - आवुक्त नगर परिषद, व्यावर

कार्यालय नगर पालिका विजयनगर जिला व्यावर राजस्थान				
क्रमांक-न.प.वि/निर्माण/स्त्री/2026/42 आम सचुना दिनांक-1-4-26				
सर्व साधारण को सूचनाएं प्रकाशित किया जाता है कि निर्माणांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उत्तर हो तो विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अपोहरस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उदा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।				
फाइल नं.	आवेदक नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
223	गीता देवी पति पुनरज साती	सुखदेव कॉलोनी ख.सं. 170, 171 मु.सं. 69	150.96 SQ.Yard	आवासीय
224	राहुल सेन पुत्र महेन्द्र कुमार	निकास पाबंधन कॉलोनी 1050/79 मु.सं. 11	90.80 SQ.Yard	आवासीय

कार्यालय नगर पालिका विजयनगर जिला व्यावर राजस्थान
क्रमांक-न.प.वि/निर्माण/2025/45 आम सचुना दिनांक-1-4-26

कार्यालय नगर पालिका विजयनगर जिला व्यावर राजस्थान				
क्रमांक-न.प.वि/निर्माण/2026/6985 आम सचुना दिनांक-25-3-26				
सर्व साधारण को सूचनाएं प्रकाशित किया जाता है कि निर्माणांकित मकान व प्लाट गृहकार्य पत्रिका में अन्तर्गत हेतु निम्न विवरत पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उत्तर हो तो विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अपोहरस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उदा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।				
फाइल नं.	आवेदक नाम	भूत आवदी/ नामानन्ता	भूखंड का विवरण	प्रयोजनार्थ
527	राजेश कुमार जेठ पुत्र राम जेठ	धनेश देवी पति तेजराज जेठ	कनैथा कॉलोनी ख.सं. 71 नि. 72 नि.73 से 78, 88, 89 नि. 90 नि.सं. 55 व 56 का दक्षिणी हिस्सा	आवासीय

कार्यालय नगर पालिका विजयनगर जिला व्यावर राजस्थान
क्रमांक-न.प.वि/निर्माण/2025/6985 आम सचुना दिनांक-25-3-26

कार्यालय नगर पालिका विजयनगर जिला व्यावर राजस्थान				
क्रमांक-न.प.वि/निर्माण/स्त्री/2026/7158 आम सचुना दिनांक-27-3-26				
सर्व साधारण को सूचनाएं प्रकाशित किया जाता है कि निर्माणांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उत्तर हो तो विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अपोहरस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उदा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।				
फाइल नं.	आवेदक नाम	भूत आवदी/ नामानन्ता	भूखंड का विवरण	प्रयोजनार्थ
513	शिवप्रसाद वैष्णव पुत्र जयदीपा प्रसाद वैष्णव	सुखदेव वैष्णव पुत्र बदौलत वैष्णव	आवादी क्षेत्र वीससा	आवासीय

कार्यालय नगर पालिका विजयनगर जिला व्यावर राजस्थान
क्रमांक-न.प.वि/निर्माण/स्त्री/2026/7158 आम सचुना दिनांक-27-3-26

कार्यालय नगर पालिका विजयनगर जिला व्यावर राजस्थान				
क्रमांक-न.प.वि/निर्माण/स्त्री/2026/7158 आम सचुना दिनांक-27-3-26				
सर्व साधारण को सूचनाएं प्रकाशित किया जाता है कि निर्माणांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उत्तर हो तो विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में मय सबूत के अपोहरस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद मियाद गुजरने पर कोई उदा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।				
फाइल नं.	आवेदक नाम	भूत आवदी/ नामानन्ता	भूखंड का विवरण	प्रयोजनार्थ
221	सुशीला कंवर पति नवील सिंह राठौड़	आवादी क्षेत्र हाउस के पीछे मु.सं. 11 का पश्चिमी हिस्सा का हिस्सा प्रा.नं. 11-बी	55.74 SQ.Yard	आवासीय
222	तारकानंद लोहार पुत्र सत्यव्रत लोहार	कॉलोनी वीससा	91.94 SQ.Yard	आवासीय

टॉपर्स छात्राओं का सम्मान

मदनगंज-किशनगढ़,(निसं)। वद्रीनारायण दरगड़ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हरमाड़ा में कक्षा 10वीं व 12वीं की प्रतिभावान छात्राओं के उत्कृष्ट परिणाम पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कक्षा 12वीं की 21 छात्राओं व कक्षा 10 की 4 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार के योग्य परिणाम प्राप्त करने पर छात्राओं को सम्मानित किया. गांव में टॉपर्स छात्राओं की रैली निकाला होसला बढ़ाया। भामाशाह श्यामसुंदर दरगड़, प्रेमचंद दरगड़, राजकुमार दरगड़, गोविंद काला, महावीर चौड़डिया, महेंद्र मेहता सहित एसडीएमसी सदस्य व प्रधानाचार्या मधुपती वैष्णव, मुक्ता दिवाकर, पूजा सैज, लतेश शर्मा ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। जगमाल गुर्जर ने प्रतिभावान छात्राओं को शिल्प, प्रमाण पत्र व माल्यार्पण कर अभिनंदन किया।

चुनाव नहीं कराना संवैधानिक संस्थाओ पर हमला

मदनगंज-किशनगढ़,(निसं)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व विधायकसभा प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जुली ने भाजपा सरकार पर आक्षेप लगाया की पंचायत व नगरीय चुनाव नहीं कराकर संवैधानिक संस्थाओ पर हमला किया जा रहा है।

राजस्थान उच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय

भीलवाड़ा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने भीलवाड़ा स्थित वक्फ संपत्ति पर अवैध रूप से बनाए गए 'दाई हलीमा मेटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल ट्रस्ट' के पंजीकरण को निरस्त करने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने अहमद अली और मोहम्मद हारून लोहार द्वारा दायर रिट याचिका (एस.जी. सिविल रिट पीटिशन नं. 6267/2026) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम, 1959 की धारा 80 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान उन मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर लागू नहीं होते जो मुस्लिम वक्फ अधिनियम द्वारा शासित हैं। अदालत ने सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग (अजमेर) द्वारा जारी आदेश और पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 02.02.2021, आयुक्त, देवस्थान विभाग (उदयपुर) द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.03.2023 एवं सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग (अजमेर) द्वारा पारित संशोधित निर्णय दिनांक 22.07.2024 के आदेशों और दस्तावेजों को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज भंडारी और अनिकेत टाटर ने दलील दी कि वक्फ संपत्ति (दरगाह गुल जी पीर) पर अवैध तरीके से ट्रस्ट बनाकर उसे देवस्थान विभाग में पंजीकृत कराया गया था, जो कि वक्फ अधिनियम और राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम के विरुद्ध धायाचिकाकर्ता मोहम्मद हारून लोहार के अनुसार, माननीय न्यायालय के इस आदेश के बाद अब - हॉस्पिटल के संचालन और देख-रेख हेतु राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा 4 सितंबर 2024 को पारित प्रस्ताव (एजेंडा नंबर 16, प्रस्ताव संख्या 13/2024) को लागू किया जाएगा। वक्फ बोर्ड द्वारा भीलवाड़ा के स्थानीय मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक नई वक्फ कमेटी का गठन किया जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के विरुद्ध संबंधित थानों में फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने हेतु कानूनी सलाह ली जा रही है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय के बाद कानून के अनुसार आवश्यक परिणाम प्रभावी होंगे।

नानी बाई रो मायरो कथा कल से

भीलवाड़ा। चित्तौड़ रोड़ स्थित कमला विहार भीलवाड़ा में राधाकृष्ण मंदिर के पास वाले पार्क में 3 दिवसीय नानी बाई रो मायरो कथा 03 अक्टूबर 2026 से 05 अप्रैल 2026 तक दोपहर 1 बजे से सांय 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। कथा वाचिका राधा स्वरूपा बाल व्यास सुश्री दीपा दाधीच भीलवाड़ा के मुखारबिन्द से कथा का वाचन होगा कथा आयोजक रामचन्द्र व्यास ने बताया कि कलश यात्रा 03 अप्रैल 2026 को प्रातः 09.15 बजे पटेल नगर 200 फिट रिंग रोड़ बालाजी से प्रारंभ होकर राधाकृष्ण मंदिर वाले पार्क में पहुंचेगी। जिसके पश्चात् कथा का प्रारंभ किया जायेगा।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आज

भीलवाड़ा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक सांसद दामोदर अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 अप्रैल को प्रातः 11:30 बजे जिला परिषद समिति कक्ष में आयोजित होगी। यह जानकारी कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने दी।

■ सांसद दामोदर अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 अप्रैल को प्रातः 11:30 बजे जिला परिषद समिति कक्ष में आयोजित होगी। यह जानकारी कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने दी

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राज			
क्रमांक-न.प.वि/निर्माण/2026/02 आम सचुना दिनांक-02.04.26			
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरव प्राम मदनगंज के खसरा संख्या-949 पर शिव प्रेम नगर निवां बावरी रोड मदनगंज किशनगढ़ के आवासीय भूखण्ड संख्या-42 व 43 कुल क्षेत्रफल 400 वर्गगज में से विकीर्णित भूखण्ड क्षेत्रफल 133.34 वर्गगज पर 1. श्रीमती रेखा देवी पति श्री सुरेश कुमावत 2. श्री रमेशचंद्र पुत्र श्री रामगोपाल 3. वृषेश वावरा पुत्र श्री सुनेंद्र कुमार वावरा ने आवेदन प्रस्तुत कर उपविभाजन चाहा गया है।			
उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार हैं-			
पूर्व में - 30 फीट का रास्ता	पश्चिम - भूखण्ड संख्या 02 व 03		
उत्तर में - भूखंड संख्या 42 एवं 43 में से विखंडित	दक्षिण - भूखण्ड संख्या 42 एवं 43 में से भूखण्ड संख्या 42 व 43 पट्ट सी		
उत्तर : उक्त उपविभाजन प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करने अन्याथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।	- प्रभावी, नगर परिषद किशनगढ़		

सफलता की उड़ान: प्रेम देवी की प्रेरणादायक कहानी, लखपति दीदी बनीं प्रेम देवी, स्वयं सहायता समूह से

जुड़कर बदली आर्थिक स्थिति भीलवाड़ा। ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर ठाण निम्बाहेड़ा खुर्द, बनेड़ा ब्लॉक की प्रेम देवी पत्नी फ्ला लाल गुर्जर आज 'लखपति दीदी' बनकर उभरी हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मिली वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन ने उनके जीवन में गहरी लम्फ बदलाव लाया है। प्रेम देवी को आराम देने बाबा स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं, जो ठाणीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत है। इनका सीएलएफ डाबला है

तथा वीओ गुरुकुपा है। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई, जिससे उन्होंने पशुपालन कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में उनके पास 6 गायें एवं 10 से 12 भैंसें हैं, जिनसे दूध एवं गोबर विक्री के माध्यम से प्रति माह 10 से 12 हजार रुपये की आय हो रही है। सरकारी योजनाओं के तहत मिले प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन ने उन्हें आय के विभिन्न स्रोत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में उन्होंने अपनी बेटी के लिए सिलाई सेंटर स्थापित करवाया, जिससे हर माह 15 से 20 हजार रुपये की आय प्राप्त हो रही है तथा स्थानीय महिलाओं को भी प्रशिक्षण मिल रहा है। परिवार की आय में उनके पति का योगदान भी महत्वपूर्ण है, जो ट्रक चालक के रूप में प्रतिमाह लगभग 40 से 50 हजार रुपये अर्जित करते हैं।

उदयपुर : अनियंत्रित टैंकर ने हाइवे पर कई वाहनों को चपेट में लिया, बड़ा हादसा टला

बताया जा रहा है कि हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, बाइक सवार युवक भी गंभीर घायल, नौ लोग हॉस्पिटल में भर्ती



हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को गाड़ियों से निकाला।



एक के बाद एक कई वाहन टैंकर में पिछे से टकरा गये।

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देवारी पावर हाउस के पास गुरुवार दोपहर भीषण हादसा हो गया। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की तरफ आ रहे एक टैंकर ने हाइवे पर देवारी पावर हाउस के पास अचानक अनियंत्रित होकर कई वाहनों को चपेट में ले लिया। इस दौरान पीछे आ रही कारों भी टैंकर से टकराए एक-दूसरे से भिड़ती चली गयीं। 10 से 12 कारों, ऑटो, टैपो और एक बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और मौके पर चीख-पुकार मच गयी।

घटना की सूचना पर आसपास के लोग बचाव के लिए दौड़े। सूचना पर

पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों से घायलों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसे में कई लोग घायल हुए हैं जबकि बाइक सवार युवक गंभीर घायल हैं, जिनमें नौ लोग हॉस्पिटल भर्ती हैं, बाकि क्षतिग्रस्त वाहन चालकों के चोटें आयी हैं, जो प्राथमिक उपचार के बाद घर चले गए। थानाधिकारी पूर्ण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि देवारी पावर हाउस के सामने हाइवे पर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की तरफ आ रहा एक टैंकर अचानक दलान पर अनियंत्रित हो गया, अनियंत्रित टैंकर ने आगे चल रहे कई वाहनों को चपेट में लिया। इस दौरान

■ पीछे आ रही कारों भी टैंकर से टकराए एक-दूसरे से भिड़ती चली गयीं, 10 से 12 कारें, ऑटो, टैपो और एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं

■ देवारी पावर हाउस के सामने हाइवे पर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की तरफ आ रहा एक टैंकर अचानक दलान पर अनियंत्रित हो गया और कई वाहनों को चपेट में ले लिया

पीछे आ रही कारों भी टैंकर से टकराए एक-दूसरे से भिड़ती चली गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया और कई लोग क्षतिग्रस्त वाहनों में फंस गए। पुलिस ने सभी

घायलों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां सुनील कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी डबोक, पूर्ण कुल्मी पुत्र कालू लाल निवासी मंगलवाड़, रमेश पुत्र जवेरा

निवासी रेवारियों का गुडा, अभिषेक शर्मा पुत्र खूबी लाल निवासी बड़ागांव, डालूराम पुत्र सुरता, निवासी आवरीमाता, रती स्टैंड, नारायण लाल पुत्र जय चंद कुल्मी, निवासी देवली, पीराना, अप्रति पालीवाल पुत्र रूप लाल निवासी देवली, मरमोत पुत्र ब्रिजकिशोर निवासी बदला रोड का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे में गंभीर घायल अमजद खान पुत्र जमालुद्दीन निवासी बैरा तहसील बाली, जिला पाली को एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रथमदृष्टया टैंकर के ड्रेक फेल होने

या दलान पर टैंकर के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ है। हॉस्पिटल में उपचारत घायलों और उनके परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बताया कि कैमिकल टैंकर भी पलटा था। तब मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर को साइड करवा दिया था और फायरब्रेड की मदद से कैमिकल को सड़क से धो दिया गया था। इसके कुछ घंटों बाद ही यहां यह भीषण हादसा हो गया।

प्लॉट की चौकीदारी कर रहे बुजुर्ग की गला काटकर हत्या

बीकानेर, (निर्सं)। चौकीदार की गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। 70 साल का बुजुर्ग एक प्लॉट की चौकीदारी कर रहा था। उसने दो दिन पहले ही यहां चौकीदारी का काम शुरू किया था। मामला जयनारायण ब्यास कॉलोनी थाना की मदन विहार कॉलोनी का है।

जानकारी के अनुसार राहगीरों ने भंवरलाल रेगार (70) निवासी शिवबाड़ी का शव पड़े देखा और पुलिस को सूचना दी थी। अज्ञात हमलावरों ने भंवरलाल रेगार की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। सूचना मिलते ही सीओ अनुष्ठा कालिया और थानाधिकारी विक्रम तिवारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू की और

■ पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल साक्ष्य जुटाये

एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि जिस प्लॉट पर मृतक चौकीदारी कर रहा था, वह जैसलमेर निवासी कुंदन सिंह का है। भंवरलाल हाल ही में 30 मार्च को ही यहां काम पर लगा था। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

अवैध पिस्टल के साथ यूपी का युवक गिरफ्तार

भोलवाड़ा, (निर्सं)। पुलिस अधीक्षक धर्मेश सिंह द्वारा जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गांधीनगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी डॉ. नेहा राव ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम अहिंसा बंगलों के सामने 80 फीट रोड पर पहुंची। वहां पुलिस जाबो को देखकर एक युवक संदिग्ध अवस्था में भागने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर युवक को दबोक लिया। पकड़े गए युवक की पहचान शिवकुमार

■ पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी

भदोरिया (20) निवासी हरदोई, उत्तर प्रदेश हाल निवासी अजादनगर भोलवाड़ा के रूप में हुई है। जाबो द्वारा युवक को तलाशी लेने पर उसके पास एक देशी पिस्टल बरामद हुई। जांच करने पर पिस्टल अनलूड पाई गई जिसमें मैग्जीन लगी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त कर ली है। आरोपी यह हथियार कहाँ से लाया था और इसे कैसे बेचने या किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, इस संबंध में पुलिस गहनता से अनुसंधान कर रही है। पुलिस अब हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़े का खुलासा

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से वर्ष 2022 में आयोजित प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मूल अभ्यर्थी ने किसी डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठकर परीक्षा दिलाई थी। इस पर एसओजी की तरफ से शास्त्रीनगर थाने में केस दर्ज कराया गया है। मामले में अग्रिम तपत्ती की जा रही है। एसओजी ग्रुप यूनिट के एएसपी स्यामसुंदर विस्नोई ने यह रिपोर्ट दी है।

प्रकरण के अनुसार मूल अभ्यर्थी दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल द्वारा परीक्षा में अपने स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाते का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि 15 अक्टूबर 2022 को आयोजित प्रथम प्रश्न पत्र (सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन) की परीक्षा में दिनेश कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि उसके स्थान पर एक अन्य अभ्यर्थी को बैठाया गया। जांच के दौरान

■ मूल अभ्यर्थी ने किसी डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठकर परीक्षा दिलाई थी

■ एसओजी की तरफ से शास्त्रीनगर थाने में केस दर्ज कराया

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल उपस्थिति पत्रक एवं ओएमआर शीट के अवलोकन में फोटो और हस्ताक्षरों में स्पष्ट भिन्नता पाई गई। प्रथम प्रश्न पत्र में हस्ताक्षर हिन्दी में तथा द्वितीय प्रश्न पत्र (हिन्दी विषय) में हस्ताक्षर अंग्रेजी में पाए गए। दोनों परीक्षाओं के दस्तावेजों में फोटो और हस्ताक्षर मेल नहीं खाते, जिससे फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। अनुसंधान में यह

भी सामने आया कि दिनेश कुमार ने अपने परिचित मनोहर लाल निवासी सांभौर जिला जालौर के माध्यम से डमी अभ्यर्थी को व्यवस्था की थी। इसके लिए प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर फोटो व हस्ताक्षर बदलकर फर्जी एडमिट कार्ड तैयार किया गया। उक्त डमी अभ्यर्थी को जोधपुर के सरदारपुरा स्थित परीक्षा केंद्र पर बैठकर परीक्षा दिलाई गई।

प्रकरण में पूछताछ में पता लगा कि द्वितीय प्रश्न पत्र हिन्दी की परीक्षा दिनेश कुमार ने स्वयं दी। पूछताछ में उसने यह स्वीकार भी किया कि प्रथम प्रश्न पत्र उसने स्वयं नहीं दिया था। यह परिवार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी यूनिट अजमेर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच एडीसीपी वेस्ट की तरफ से की जा रही है।

कोटा, (निर्सं)। युवक की हत्या के साढ़े छह साल पुराने मामले में महिला उल्कीडन न्यायालय क्रम-1 न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मामले में दो महिलाओं सहित 12 जनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार 31 अगस्त 2018 को फरियादी जाहिर हुसैन ने उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उसका मामा अब्दुल अजीज उर्फ पप्पू जो बोम्बे योजना में परिवार सहित रहता है, रिपोर्ट में कहा कि उसके मामा अब्दुल अजीज उर्फ पप्पू का उसके पड़ौसी रमजानी के बीच बकरे के मामले को लेकर विवाद हो गया था। वह व उसका भाई इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू तथा दो मित्र यशपाल व कालू उसके मामा के घर मिलने आये थे।

फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि उसका भाई इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू व यशपाल दुकान पर कुछ सामान लेने गये, उसी समय बकरे की लड़ाई की रंजिश के चलते रमजानी ने अपने दो बेटे मुख्तार मोहम्मद, मुशताक मोहम्मद उर्फ भुरू, एवं शोयब, सद्दाम, जहीर, शाहरूख, मुबारिक व सात-आठ अन्य ने चाकू, लकड़ियां व धारदार हथियार लेकर एकराय होकर जान से मारने की नियत से उसके भाई इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू पर हमला कर दिया। जहीर, शाहरूख व मुबारिक ने उसके भाई के उपर चाकू से ताबातोड़ वार किये। बीच बचाव में यशपाल को भी चोट आई, हमलावर

■ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, मामले में 25 गवाहों के बयान दर्ज कराये

हमला कर मौके से फरार हो गये। रिपोर्ट में कहा कि हमले में गंभीर रूप से घायल हुए इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू को उपचार के लिये निजि अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसके भाई इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर हत्या के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पुलिस ने मामले में कार्यवाही व अनुसंधान करते हुए बोम्बे योजना निवासी रमजानी मोहम्मद (57), उसकी पत्नी फरजाना (43), दो बेटे मुशताक मोहम्मद उर्फ भुरू (29), मुख्तार मोहम्मद (31) एवं मुबारिक अली (26), लाडपुरा निवासी सद्दाम खान (32), किशोरपुरा निवासी जहीर खान (35), बोम्बे योजना निवासी शाहिन खानम (37), शाहरूख उर्फ लंगडा (26), नईमुद्दीन उर्फ शोयब (26), शाहदत (30) एवं लाडपुरा निवासी शाहरूख (32) को गिरफ्तार किया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, मामले में 25 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।

श्रीगंगानगर, (निर्सं)। प्रेमी ने साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका के पति की हत्या कर दी। आरोपी ने पति पर सोते समय धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पत्नी के अवैध संबंधों का पता चलने के बाद पति की एक दिन पहले आरोपी प्रेमी के साथ बहस हुई थी। जिसके बाद महिला ने प्रेमी से पति की हत्या करवा दी।

एसएचओ बलवंत कुमार ने बताया कि बुधवार रात एक बजे सूचना मिली कि एक गांव में स्थित चौधरी ईट भट्टे पर दो युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और घायल भादर सिंह, और अमरीक को रावला अस्पताल पहुंचाया। जहां से गंभीर हालत में दोनों को बीकानेर रेफर कर दिया। भादर सिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि अमरीक सिंह को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी सतनाम अपने साथियों के साथ भादर सिंह के कमरे पर पहुंचा और मारपीट के बाद मौके से फरार हो गया। मृतक भादर सिंह के बड़े भाई वीर प्रताप सिंह ने बताया कि मेरे भाई भादर सिंह की पांच साल पहले मनप्रीत कौर से शादी हुई थी। दोनों की एक साल की बेटी है। भादर सिंह (मृतक) एक ईट भट्टे पर ट्रैक्टर चलाने का काम

■ पत्नी के अवैध संबंधों का पता चलने के बाद पति की एक दिन पहले आरोपी प्रेमी के साथ बहस हुई थी

करता था। इसी भट्टे पर सतनाम सिंह पुत्र बख्तावर सिंह भी काम करता था। आठ महीने पहले मनप्रीत और सतनाम सिंह के बीच में अवैध संबंध शुरू हो गया। वीर प्रताप को जब मनप्रीत के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने उसे काफी समझाने की कोशिश की। मगर मनप्रीत ने सतनाम से मिलना बंद नहीं किया। एक महीने पहले मनप्रीत के मामा के साथ उसने फिर से समझाया, इस पर उसने अपनी गलती मान ली और आश्वासन दिया कि वह सतनाम से नहीं मिलेगी। पत्नी के अवैध संबंध को लेकर भादर सिंह काफी तनाव में रहता था। कुछ दिन पहले ही मनप्रीत अपनी बेटी को लेकर पीहर खाजूवाला चली गईं।

वीरप्रताप ने बताया कि बुधवार को मनप्रीत से अवैध संबंधों को लेकर भादर का सतनाम से विवाद हुआ। इसके बाद मनप्रीत ने सतनाम को मेरे भाई भादर की हत्या के लिए उकसाया। इसके बाद रात

1 बजे सतनाम सिंह, गुरदास सिंह, गुरमीत सिंह बावरी, गुरजेंट, गुरचरण सिंह ने एकराय होकर भट्टे पर अपने कमरे में सो रहे मेरे भाई भादर सिंह और उसके साथ अमरीक सिंह पर हमला कर दिया। चौधरी ईट भट्टे के मालिक कुलदीप भाभू ने बताया कि ईट भट्टे पर काम करने वाले कुछ मजदूरों ने बताया कि बुधवार शाम भादर सिंह और सतनाम सिंह के बीच कहासुनी हुई थी। इस पर कुछ मजदूरों ने दोनों पक्षों से समझाइश कर एक बार की मामले को शांत कर दिया। इसके सतनाम सिंह मौके से चला गया। बुधवार रात में भादर सिंह अपने डॉक्टर के ड्राइवर अमरीक सिंह (35) साथ ईट भट्टे पर बनी झुग्गी में सो रहा था। रात करीब एक बजे सतनाम सिंह अपने भाई और 2-3 अन्य लोगों के साथ उसकी झुग्गी में आया। इस के बाद लाठी, डंडों और गंडासी से सो रहे भादर सिंह और अमरीक सिंह में ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोर सुनकर जब बाकी लोग जाग गए तो आरोपी मौके से भाग निकले।

रावला एसएचओ बलवंत कुमार ने बताया कि मृतक और घायलों के परिजनों के द्वारा अभी तक कोई लिखित रिपोर्ट दी गई है। घायल अमरीक के बयान ले लिए हैं। आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।

दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई

कोटा, (निर्सं)। नाबालिग से दुष्कर्म के लामबग 14 माह पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम- 4 न्यायालय ने पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने 22 फरवरी 2025 को ग्राभीण के एक

■ पॉक्सो कोर्ट क्रम- 4 न्यायालय ने आरोपी को 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया

थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा कि 21 फरवरी 2025 को उसकी छोटी बहन को दूढ़ने के लिए वह पड़ौसी युवक के घर गई थी, वहां

पर युवक ने उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया, पुलिस ने मामले में कार्यवाही व अनुसंधान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज किये गये और 28 दस्तावेज पेश किए गए।

युवक का शव मिला

टोंक, (निर्सं)। उनियारा थाना क्षेत्र में गुरुवार को टोंक-सवाई माधोपुर नेशनल हाइवे की पुलिया के नीचे करीब डेढ़ फीट के पानी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस शव पर बाहरी चोट के निशान नहीं थे उसके दोनों पैर के अंगुठे प्लास्टिक की रस्सी से आपस में बंधे थे। सूचना मिलने के

■ शव को शिनाख्त के लिए उनियारा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया

बाद उनियारा डीएसपी आकांक्षा चौधरी मौके पर पहुंची और शव को शिनाख्त के लिए उनियारा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। डीएसपी आकांक्षा चौधरी ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिलने के बाद टोंक-सवाई माधोपुर नेशनल हाइवे-552 पर कामधेनु सिकल और कोर्ट के बीच की बाईपास पर गलवा नगर की पुलिया के नीचे भरे पानी में एक युवक का शव मिला, इसके बाद उनियारा थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच कर जांच की। इसके बाद शव को पानी से बाहर निकलवाया, जो दो दिन पुरानी लग रही है। बाहरी चोट के निशान नजर नहीं आए और न ही किसी से लड़ाई झगड़े में होने वाली चोट है। जिसके बाद उनियारा पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है।

अजमेर-ब्यावर नेशनल हाइवे पर बायोडीजल टैंकर में भीषण आग लगी



आग की लपटें दूर तक दिखाई दीं। वहीं दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।



घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हाइवे पर यातायात रोक दिया और वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट कर ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित किया। हादसे के दौरान पुलिस की बार-बार चेतावनी के बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए सुलगते टैंकर के बेहद करीब से दुपहिया वाहनों पर निकालते हुए नजर आए। इस लापरवाही के चलते हाइवे के दोनों ओर करीब डेढ़ से दो किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा।

■ चालक और खलासी ने टैंकर को सड़क किनारे खड़ा किया और सुरक्षित बाहर निकल गए

■ टायर फटने के कारण लगी आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया और टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया

अजमेर, (कासं)। जिले के मांगलियाबास क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ब्यावर से अजमेर की ओर आ रहा बायोडीजल से भरा एक टैंकर अचानक आग की चपेट में आ गया। टायर फटने के कारण लगी आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया और टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। आग लगते ही टैंकर चालक और खलासी ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को तुरंत किनारे खड़ा किया और सुरक्षित बाहर निकल गए। उनकी सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होने

से टल गया। बताया जा रहा है कि टैंकर गुजरात से अजमेर की ओर आ रहा था। जानकारी के अनुसार हादसा अजमेर-ब्यावर नेशनल हाइवे-8 पर सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुआ।

सूचना मिलते ही मांगलियाबास थाना पुलिस और दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हाइवे पर यातायात रोक दिया और वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट कर ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित किया। हादसे के दौरान पुलिस की बार-बार चेतावनी के बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए सुलगते टैंकर के बेहद करीब से दुपहिया वाहनों पर निकालते हुए नजर आए। इस लापरवाही के चलते हाइवे के दोनों ओर करीब डेढ़ से दो किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा।

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर जिले में खेत पर काम कर रहे किसान पर एक पैथर ने हमला कर दिया। किसान को संघर्ष करता देख कुछ बंदरों ने पैथर पर अटैक कर दिया और पैथर को वहां से भगाकर किसान की जान बचाई। इस घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। लोगों का कहना है कि किसान की गृहार सुनकर महाबली ने अपनी वानर सेना भेजी। किसान भी हनुमानजी का भक्त है और गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव भी है।

जानकारी के अनुसार लोसिंग गांव निवासी वार्ड पंच तुलसीराम पालीवाल (55) सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे अपने खेत में गेहूं की फसल काट रहे थे। काम के बाद वे पास ही पेड़ की छाया में आराम करने बैठे तभी झाड़ियों

■ हमले में किसान के हाथ और पीठ पर मामूली खरोंचे आईं, आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और तुलसीराम को लोसिंग के अस्पताल पहुंचाया

दो बाल अपचारी डिटेल किये

उदयपुर, (निर्सं)। शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में अपचारी पर चाकू से प्राणघातक हमला करने के मामले में विधी से संघर्षरत दो बाल आपचारियों को सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह मय टीम ने डिटेल किया।

■ हमले में किसान के हाथ और पीठ पर मामूली खरोंचे आईं, आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और तुलसीराम को लोसिंग के अस्पताल पहुंचाया

में छिपे पैथर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। पैथर ने उनकी गर्दन पर पंजा मार दिया, जिससे वे घबरा गए। तुलसीराम पालीवाल ने बताया कि अचानक हुए हमले के दौरान पास के पेड़ों पर बैठे बंदरों का झुंड शोर मचाते हुए नीचे आ गया और पैथर पर हमला

कर दिया। इसी बीच आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। बंदरों के हमले और लोगों को आता देखकर पैथर मौके से भाग निकला। पीड़ित ने भावुक होकर बताया कि दो बंदर तो जैसे हनुमान जी बनकर आए और मेरी जान बचा ली। हमले में उनके हाथ और पीठ पर मामूली खरोंचे आईं हैं। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और तुलसीराम को लोसिंग के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर पैथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव हो सके।

Office of the Executive Engineer, PHED, Distt Rural Div I Bikaner
 Office ID - eephdn1bkn@gmail.com, Contact No. 0151-2941473
 No.5966-85, Date: 27/03/2026

Notice Inviting Bid : 145-150/2025-26
 Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 10.04.2026 upto 02.00 PM. Other particulars of bid may be visited on the Procurement Portal http://eproc.rajasthan.gov.in and http://sppp.raj.nic.in of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 248.20 Lacs.
 UBN No. PHE2526WSOB15958, PHE2526WSOB15959, PHE2526WSOB15960, PHE2526WSOB15961, PHE2526WSOB15962, PHE2526WSOB15963
 जल सीमित है, इसकी बचत करें।
 (Aditya Shrivastava)
 Executive Engineer
 PHED, Distt (R) Div I Bikaner

DIPR/C/6330/2026

सीएम के सक्रिय प्रयास व प्रभावी समन्वयन से केन्द्र से प्राप्त राशि में उल्लेखनीय वृद्धि

मार्च माह में ही केन्द्र ने राज्य को लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि की जारी

जयपुर, (निस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पेयजल, कृषि व आधारभूत संरचना आदि क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

मार्च माह में ही राज्य को केन्द्र सरकार के माध्यम से लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि प्राप्त हुई। प्राप्त राशि से केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर रही है। केन्द्र सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम फोर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (सास्को) योजना की शुरुआत की थी।

इस योजना के अंतर्गत राज्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 हजार 548 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है,



मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पेयजल संबंधी दिशा निर्देश दिए।

जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष (2020-21 से 2022-23 तक) में यह राशि मात्र 7 हजार 290 करोड़ रुपये ही थी।

एसएनए-स्पर्श पर संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान

राशि 13 हजार 658 करोड़ रुपये जारी की गई है। इसी प्रकार वित्त आयोग की सिफारिश एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15 हजार 666 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री के विशेष

प्रयासों से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष गत पांच वर्षों में सर्वाधिक 2 हजार 693 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2021-22 में 2 हजार 440 करोड़ और वर्ष 2022-23 में 2 हजार 138 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे।

■ पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक राशि हुई प्राप्त

करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये थे। उल्लेखनीय है कि एसएनए-स्पर्श पर संचालित योजनाओं के संबंध में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य रहा है। जिसके फलस्वरूप केन्द्र ने प्रदेश को सास्की योजनाओं के तहत 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है। समग्र शिक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 हजार 972 करोड़ रुपये और 2024-25 में 3 हजार 93 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2021-22 में 2 हजार 440 करोड़ और वर्ष 2022-23 में 2 हजार 138 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे।

विवाह स्थलों की पार्किंग में राहत देने की मांग की



जयपुर विवाह स्थल समिति, जयपुर के पदाधिकारीओं ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को मांगों को लेकर ज्ञापन साँपा।

जयपुर, (निस)। आज सिटी पैलेस में जयपुर विवाह स्थल समिति, जयपुर के पदाधिकारीओं ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ज्ञापन पत्र देकर नगर निगम द्वारा विवाह स्थलों पर पार्किंग अनिवार्य करने के नियम में राहत देने का अनुरोध किया।

समिति ने पत्र में बताया कि विवाह स्थल समिति जयपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों से कार्यरत है और यहाँ आयोजित विवाह समारोहों में कई विवाह स्थलों में पार्किंग की कोई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। नगर निगम के नए नियमों के अनुसार 25

प्रतिशत पार्किंग विवाह स्थलों में अनिवार्य कर दिया गया है जबकि छोटे विवाह स्थलों पर यह सुविधा प्रदान नहीं है। छोटे विवाह स्थलों में मध्यम एवं गरीब वर्ग के लोग अपने शादी समारोह आदि आयोजन कम खर्च में कर लेते हैं अब इन गार्डनो के बंद होने से मध्यम एवं गरीब वर्ग पर आर्थिक भार पड़ेगा। समिति ने यह भी अवगत कराया कि वर्ष 2026-27 के लिए सैकड़ों विवाह स्थलों का नवीनीकरण किया जाना है लेकिन पार्किंग नियमों के कारण विवाह स्थलों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है।

अतिरिक्त सचिव चालीस हजार की रिश्त लेते गिरफ्तार

जयपुर, (निस)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की सीकर टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी नीमकाथाना के अतिरिक्त चार्ल्स सचिव एवं सीकर मंडी के अतिरिक्त सचिव रणधीर सिंह को चालीस हजार रुपए की रिश्त लेते री हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि आरोपी रणधीर सिंह परिवारी के परिवर्जितों के नाम चार दुकानों के लाइसेंस जारी करने की एवज में रिश्त की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी चौकी सीकर ने मामले का सत्यान किया, जिसमें आरोपी द्वारा अस्सी हजार रुपए की रिश्त मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक सुभाष मोल एवं उनकी टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी को परिवारी से चालीस हजार रुपए की रिश्त राशि लेते हुए री हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

संदेश नायक ने संभाला जयपुर जिला कलेक्टर का पदभार

सुशासन, पारदर्शिता और जनकेन्द्रित प्रशासन को दी प्राथमिकता

जयपुर, (निस)। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने गुरुवार को जयपुर जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने उन्हें औपचारिक रूप से कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट में एक गरिमायुक्त वातावरण में पदभार ग्रहण की प्रक्रिया सम्पन्न हुई। पदभार संभालने के पश्चात संदेश नायक ने कहा कि जयपुर जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिले की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए गर्व के साथ-साथ एक बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि जिला प्रशासन की समर्पित टीम के सहयोग से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि उसे धरातल पर उतारना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य



संदेश नायक ने गुरुवार को जयपुर जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया।

आमजन को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। इसी क्रम में जयपुरवादी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं परिणामोन्मुखी बनाया जाएगा, ताकि प्रत्येक परिवेदान को त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन के साथ संवाद को प्राथमिकता देते और संवेदनशीलता के साथ

पूर्व उपमहापौर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

जयपुर, (निस)। प्रदेश संयोजक स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ एवं पूर्व उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स (यूडी टैक्स) में पेनल्टी एवं ब्याज छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की है।

पुनीत कर्णावट ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स शहरी निकायों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे नगरीय विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में सहायता मिलती है। राज्य सरकार द्वारा इस कर के बकाया भुगतान पर पेनल्टी एवं ब्याज में दी ग छूट, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी थी, एक सरहनीय कदम रहा है। इसके करदाताओं को राहत मिलने के साथ-साथ राजस्व संग्रह में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि मार्च माह में वेतनभोगी, व्यापारी एवं उद्यमियों पर विभिन्न करों एवं वित्तीय दायित्वों का अधिक दबाव रहता है, जिसके कारण अनेक करदाता समय पर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स का भुगतान नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007 से 2026 तक की अवधि के लिए एकमुश्त देय राशि अधिक होने से भी भुगतान में कठिनाई उत्पन्न हुई है।

सार-समाचार

डॉ. रश्मि शर्मा ने समग्र शिक्षा राजस्थान के रूप में कार्यभार संभाला



जयपुर, (निस)। भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी आएएस डॉ. रश्मि शर्मा ने 2 अप्रैल को राजस्थान शिक्षा विभाग में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा राजस्थान के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उसी दिन विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। बैठक में प्रेजेटेशन के माध्यम से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की प्रशासनिक व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं, गतिविधियों एवं अन्य प्रमुख बिंदुओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त ने विभिन्न कॉम्पोनेंट्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश दिए तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका फोकस राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त, समावेशी एवं परिणामोन्मुख बनाने पर रहेगा। डॉ. शर्मा के पास प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने पूर्व में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक विकास से जुड़े विषयों पर उल्लेखनीय कार्य किया है। बैठक में वित्त सलाहकार अनुपमा शर्मा, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम श्रीमती सीमा शर्मा, द्वितीय श्री अशोक कुमार मीणा, सहित विभिन्न उपायुक्त, उपनिदेशक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पंचायतों और निकायों के चुनाव तय समय में नहीं कराने पर अफसरों को अवमानना नोटिस

जयपुर, (निस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी प्रदेश की ग्राम पंचायतों व निकायों के चुनाव 15 अप्रैल तक नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और आयोग सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढा की अवमानना याचिका पर दिए। इसके साथ ही अदालत ने पंचायत चुनाव के मामले में गिरिजामाता सूची को अफसरों को अवमानना याचिका को इस याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चुनाव की तय समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि यह सीधे तौर पर अदालती आदेश की अवमानना है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। अवमानना याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 14 फरवरी 2025 को निर्देश दिया था कि प्रदेश की ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक कराए। इसके साथ ही राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। इस आदेश के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल से मना करते हुए 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था। याचिका में कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए गत फरवरी की महान में जारी किए कार्यक्रम में 22 अप्रैल तक अंतिम मसदाता सूची जारी करना तय किया है। इससे साफ है कि किसी भी सूत्र में 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते हैं। वहीं गिरिजामाता सूची को अंतिम मसदाता प्रेषित देवाने में अदालत को बताया कि अदालत ने निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के आदेश दिए थे। पंचायत चुनाव की अंतिम मसदाता सूची जारी कर दी गई है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ नहीं कराए जा रहे। ऐसे में अवमानना कर्ता अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना करने को लेकर दंडित किया जाए।

सरस ब्राण्ड से मिलते-जुलते नाम से घी के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक

जयपुर, (निस)। वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 2 जयपुर महानगर द्वितीय ने राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के पक्ष में बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने आरसीडीएफ के प्रतिष्ठित ब्राण्ड सरस के नाम से मिलते-जुलते ब्राण्ड श् श्री पार्व्व सरस श् ब्राण्ड के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने सरस ब्राण्ड को सुप्रसिद्ध ट्रेड मार्क मानते हुए इसके नाम का दुरुपयोग करने पर पाली की फर्म मैसर्स रत्नदीप मिलक प्रोडक्ट्स को क्षतिपूर्ति के रूप में आरसीडीएफ को 50 हजार रुपये के भुगतान का आदेश भी पारित किया है। न्यायालय ने फर्म को श्री पार्व्व सरस के उत्पादन से संबंधित सभी सामान को नष्ट करने के आदेश भी दिये हैं। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन को ओर से अधिवक्ता यशवर्धन सिंह ने माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आरसीडीएफ का सरस ब्राण्ड एक प्रतिष्ठित ब्राण्ड है और आम उपभोक्ता इसकी गुणवत्ता पर पूरा भरोसा करते हैं। प्रतिवादी फर्म ने समान और शायक रूप से मिलते जुलते ट्रेड मार्क श्री पार्व्व सरस ब्राण्ड के नाम से घी का उत्पादन कर आरसीडीएफ के पंजीकृत ट्रेड मार्क का उल्लंघन किया। आरसीडीएफ द्वारा माननीय न्यायालय में सरस से मिलते-जुलते नाम से घी के उत्पादन एवं क्रियेय पर रोक लगाने और प्रतिवादी को दंडित किया जाने के लिये वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय के इस निर्णय से प्रतिष्ठित सरस ब्राण्ड के नाम से मिलते-जुलते ब्राण्ड्स से आम उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त सरस ब्राण्ड का घी एवं उत्पाद आसानी से उपलब्ध होंगे।

युवक की हत्या कर प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर शव खाली प्लॉट में फेंका

जयपुर, (निस)। करघनी थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर उसके शव को प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर खाली प्लॉट में ले जाकर फेंक दिया और शिनाखा नहीं होने के कारण केमिकल डालकर आग लगा कर जला दिया। लेकिन शव पूरा नहीं जल पाया और आग बुझ गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने अद्वर्जला युवक का शव पड़ा देख मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर भी को कावैटिया अस्पताल के मृत्युघर में भिजवाया। जहां से पुलिस ने शव को शिनाखा कर मामले की जानकारी उसके परिवर्जितों को दी। एड.डीसीपी (वेस्ट) राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को स्थानीय लोगों ने खाली प्लॉट में अद्वर्जला युवक का शव पड़ा होने की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने निवारक पुलिसिया से कुछ ही दूरी पर एक खाली प्लॉट से युवक का अद्वर्जला शव बरामद किया। पुलिस ने घटना स्थल से एफएएसएल टीम व डॉग स्क्वाड टीम की सहायता से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि युवक की किसी दूसरी जगह हत्या की गई, जिसके बाद प्लास्टिक के एक बड़े कट्टे में शव को बांधकर देर रात यहां फेंककर ठिकाने लगाया गया। मृतक की पहचान शिवाके के लिए उसके मुंह और शरीर पर किसी ज्वलनशील केमिकल को डालकर आग लगाई गई है।

न्यू टैक्स वसूली में सरकार की सख्ती, जनता बेहाल राहत की अवधि बढ़ाने की मांग तेज

जयपुर, (निस)। राजस्थान में नगरीय विकास कर (टैक्स) को लेकर सरकार की सख्त नीति अब आम जनता पर भारी पड़ रही है। एक तरफ सरकार राजस्व बढ़ाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर हजारों करदाता पेनल्टी और ब्याज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। नगर निगम जयपुर में नेता प्रतिपक्ष रहे गिरिजा खंडेलवार ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार को सीधे तौर पर घेरेते हुए कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक पेनल्टी और ब्याज में छूट देकर राहत का दिखावा जरूर किया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस अवधि में अधिकांश लोग भुगतान ही नहीं कर पाए।

आमजन के आशियाने का सपना साकार करना रहेगी प्राथमिकता : आवासन आयुक्त

जयपुर, (निस)। आमजन के आशियाने के सपने को साकार करना आवासन मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह कहना है आवासन

■ आवास भवन का किया दौरा, व्यवस्थाओं का लिया निरीक्षण

आयुक्त श्री अरविंद पोसवाल का। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अरविंद पोसवाल ने को आवासन मंडल के मुख्यालय आवास भवन में आयुक्त का कार्यभार संभाला। उन्होंने मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक लेकर चल रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी ली। पोसवाल ने मंडल टीम द्वारा पिछले वर्षों में किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए बधाई दी और इस गति को



अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक लेकर ली विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी।

निरंतर बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि आवासन मंडल ने गुणवत्तायुक्त और समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए आमजन का विश्वास पाया है। सभी अधिकारिण इस विश्वास को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि टीम

भावना के साथ काम करते हुए ही हम आवासन मंडल की हमारा प्रयास-सबको आवास थीम को भूबलूट करते हुए आमजन को सुविधा संपन्न और गुणवत्ता युक्त आवास उपलब्ध करा सकते हैं।

जयपुर में अवैध एलपीजी रिफिलिंग का भंडाफोड़

जयपुर, (निस)। जयपुर कमिश्नरेंट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (क्राइम ब्रांच सीएसटी) ने शहर में अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साक्ष्य ही पुलिस टीम ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव नैन ने बताया कि पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल की मार्गदर्शन में विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशंस) ओमप्रकाश के निर्देशन के सुपरविजन में सीएसटी टीम ने यह कार्रवाई की। टीम ने विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में रसद विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस उपायुक्त (अपराध) के अनुसार श्रीराम कच्ची बस्ती रोड नंबर 17 पर अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही थी।

'पेपर लीक या नकल की सूचना देने पर मिलेगा एक लाख का इनाम'

जयपुर, (निस)। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक (एसआई) भती परीक्षा 2025 को लेकर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आगामी 05 और 06 अप्रैल 2026 को राज्य भर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले तत्वों की सटीक जानकारी देता है, तो उसे एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। एसओजी ने इन आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9530429258 भी जारी किया है, जिस पर मैसेज के जरिए सूचना साझा की जा सकती है। पुलिस को अंदेशा है कि

■ पुलिस को अंदेशा है कि कुछ आपराधिक तत्व परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं

कुछ आपराधिक तत्व परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। विशेष रूप से प्रश्न पत्र लीक करने के प्रयास, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए नकल, असली अभ्यर्थी के स्थान पर डमी कैंडिडेट (मुझा भाई) बैनाना और अन्य किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, जयपुर का होगा। इस आदेश की प्रतिलिपि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

जयपुर पासपोर्ट ऑफिस को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी

जयपुर, (निस)। जयपुर स्थित ज्ञानाला के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। गुरुवार को पासपोर्ट ऑफिस की अधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए धमकी भरे लेटर में बम विस्फोट की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। एसीपी (गांधीनगर) नारायण बाजिया ने बताया कि धमकी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एहतियातन कार्यालय परिसर को खाली करवाया गया। इसके बाद एटीएस के बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि, जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संहिध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। वहीं धमकी के बाद पासपोर्ट कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस तरह की

धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए हर एंगल से जांच की जा रही है। ई-मेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मेल किस लोकेशन और डिवाइस से भेजा गया। गौरतलब है कि पिछले 23 दिनों में यह तीसरा मौका है। जब जयपुर पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर के अलावा अलवर और अजमेर के पासपोर्ट सेवा केंद्रों को भी इसी तरह के धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं। तलाशी अभियान के दौरान एक दिलचस्प स्थिति भी सामने आई। जब पासपोर्ट ऑफिस के कुछ कर्मचारी टिफिन खोलकर भोजन करने लगे। जिन्हें सुरक्षा में लगे जवानों ने तत्काल रोका और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि जयपुर में पिछले कुछ समय से सरकारी और निजी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है।

विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान गांव व शहरों के सुनियोजित विकास का रोडमैप

जयपुर, (निस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान के अंतर्गत स्थानीय लोगों से सुझाव लेते हुए वर्ष 2030, 2035 एवं 2047 तक की आवश्यकताओं के अनुरूप गांव एवं शहरों के विकास का मास्टर प्लान एवं रोडमैप तैयार किया जा रहा है। मैपिंग इस अभियान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान की डिजिटल मैपिंग के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) से सहयोग प्राप्त करते हुए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर बीआईएसएजी (एन) द्वारा विभिन्न विभागीय परियोजनाओं में डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के संबंध में बैठक का संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान में इस तकनीक से गांवों और शहरों की वास्तविक जरूरतों को



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीआईएसएजी (एन) द्वारा विभिन्न विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा की।

समझकर योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही, क्षेत्र विशेष की मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए प्लानिंग बनाने में यह सहायक होगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के तहत डिजिटल मैपिंग का अधिक से अधिक

उपयोग करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 19 मार्च से 15 मई तक संचालित इस अभियान के अंतर्गत 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायत एवं 10 हजार से अधिक शहरी वार्ड शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआईएसएजी (एन) द्वारा

■ पीएम गतिशक्ति के माध्यम से विकास परियोजनाओं की हो सकेगी रीयल टाइम मॉनिटरिंग

पीएम गतिशक्ति के तहत विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी विभागों की परियोजनाओं को एकीकृत करके कार्यों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग संभव है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए परियोजनाओं में विकास से लेकर क्रियान्वयन तक हर स्तर पर इसका उपयोग किया जाए।

अलवर और अजमेर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली

पासपोर्ट कार्यालयों को खाली करवाकर बम निरोधक दस्ते और अन्य एजेंसियों ने जांच की

अलवर/अजमेर, (निसं)। अलवर में पासपोर्ट कार्यालयों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा-तफरी मच गई। धमकी भरे संदेश में दोपहर दो बजे ब्लास्ट होने की बात लिखी गई, जिसके बाद पुलिस ने एहतियातन सभी कर्मचारियों और आम लोगों को तुरंत बाहर निकाल दिया। मौके पर सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और पूरे क्षेत्र को घेर लिया।

जानकारी के अनुसार अलवर पासपोर्ट ऑफिस को इस महीने में तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी दो बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे ऑफिस को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मुछ गेट को बंद कर किसी भी व्यक्ति को एंट्री पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते में यह दूसरी बार है, जब इस तरह की धमकी मिली है। ई-मेल के जरिए भेजी गई इस धमकी में राजस्थान के कई पासपोर्ट कार्यालयों को निशाना बनाने की बात कही गई है। मेल में लिखा गया कि दोपहर दो बजे से पहले ऑफिस खाली कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद बम विस्फोट किया जाएगा। साथ ही धमकी देने वाले ने कर्नाटक की राजनीति से जुड़े किसी पुद्द का भी जिक्र किया है।



भरतपुर में करोड़ों की ठगी मामले में

इस दौरान पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो अपने काम के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने सभी लोगों को गेट के बाहर ही रोक दिया और स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करने के लिए कहा।

कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर ओमप्रकाश ने बताया कि फिलहाल पूरे परिसर की बारीकी से जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल ऑफिस का कामकाज भी रोक दिया गया है।

अजमेर संवाददाता के अनुसार :- पासपोर्ट मुख्यालय जयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को एक धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद अजमेर स्थित पासपोर्ट कार्यालय में हड़कंप मच गया। ई-मेल में कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र में तत्काल सतर्कता बढ़ा दी गई।

■ अलवर और अजमेर पासपोर्ट ऑफिस में तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली

■ पुलिस ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है और साइबर टीम को मदद से मामले की गहन जांच की जा रही है

आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते और अन्य एजेंसियों द्वारा पूरे कार्यालय परिसर की बारीकी से जांच की गई। करीब लंबे समय तक चली तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है और साइबर टीम को मदद से मामले की गहन जांच की जा रही है।

बीकानेर से खाड़ी देशों को जाने वाला 100 कंटेनर माल का निर्यात ठप

बीकानेर, (निसं)। खाड़ी देशों में सालाना 50 हजार टन बीकानेरी भुजिया समेत अन्य आइटम जाते हैं, लेकिन युद्ध के कारण करीब 100 कंटेनर निर्यात ठप हो गया है। एक कंटेनर में 25 टन माल आता है। दुबई व अन्य देशों में कंटेनर फंस गए हैं। दुबई के क्रूज टर्मिनल पोर्ट राशिद बंदरगाह पर कंटेनर का किराया भी 120 डॉलर से बढ़कर 2200 डॉलर तक पहुंच गया है।

■ दुबई के क्रूज टर्मिनल पोर्ट राशिद बंदरगाह पर कंटेनर का किराया भी 120 डॉलर से बढ़कर 2200 डॉलर तक पहुंचा

■ 'हर महीने 15 से 20 कंटेनर भुजिया, पापड़ और नमकीन का एक्सपोर्ट होता है, जो फिलहाल बंद है'

इसके अलावा अन्य देशों में हर महीने करीब 80 कंटेनर माल भेजा जाता है, वो भी अटक आ रहा है। कुछ दिन ऐसे ही हालात रहे तो भुजिया, पापड़ की कीमतों में 3 रुपये प्रति किलो का उछाल आ सकता है। अभी नमकीन उत्पादन पर

असर नहीं है। वहीं, नोखा के प्रमुख एक्सपोर्टर राजेश कुमार झंवर ने बताया कि हमने 850 डॉलर में कंटेनर किराए पर लेकर जीरा, मेथी दाना, मूंगफली दाना इराक भेजे थे, लेकिन माल बीच में ही कहीं

उतार दिया गया। अब शिपिंग कंपनी वॉर चार्ज के नाम पर 4 हजार डॉलर मांग रही है। युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में ऊन के कंटेनर अटक गए हैं। ऊन व्यवसायी ऋषभ बोथरा ने बताया कि बीकानेर में 700-800 कंटेनर ऊन मॉडिल ईस्ट से आता है। 11 मार्च को कुछ कंटेनर पहुंचे हैं, जो हीमूर्ज पर फंसे हुए थे। अभी भी काफी कंटेनर बीच में ही अटके हुए हैं। वॉर चार्ज के नाम पर शिपिंग कंपनियों काफी पैसा मांग रही है। उन्होंने बताया कि युद्ध की वजह से बीकानेर का कारपेट उद्योग भी प्रभावित हुआ है।

पति ने पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंका, थाने पहुंचकर सरेंडर किया

हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ, आरोपी पति हरप्रीत हिरासत में

बीकानेर, (निसं)। एक पति ने पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया। इतना ही नहीं मर्डर के दो घंटे बाद थाने पहुंचा और सरेंडर कर बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मामला जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में गुरुवार का है। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन, पुलिस ने आरोपी पति हरप्रीत को हिरासत में ले लिया है।

■ प्रारंभिक जानकारी में आपसी विवाद के चलते ही पति के पत्नी की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है

दोपहर करीब 1:15 बजे हरप्रीत सिंह निवासी 8 डीडब्ल्यूडी थाना दंतौर, खाजूवाला थाने पहुंचा। यहां बताया कि उसने अपनी पत्नी जसवंत को ही हत्या कर दी है। आरोपी ने बताया कि पत्नी का शव चक 9 डीडब्ल्यूडी के एक खेत

में पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो जसवीर का शव झाड़ियों के बीच पड़ा था। इसके बाद एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और घटनास्थल से सबूत शामिल किए।

चावला व थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत बीकानेर में महानिदेशक पुलिस की संभागा स्तरीय बैठक में गए हुए थे। सूचना मिलने के बाद दोनों अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन प्रारंभिक जानकारी में आपसी विवाद के चलते ही पति के पत्नी की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है।

घटना के समय डिप्टी अमरजित

डार्क जोन में चल रही वाटर कंपनी को फिर मिला कोर्ट का नोटिस

अलवर, (निसं)। अवैध रूप से अलवर के डार्क जोन आलापुर गांव में चल रही एक्वाफिल वाटर फैक्ट्री को कोर्ट नोटिस तामील नहीं करने पर दूसरा नोटिस जारी किया है और कंपनी को 28 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। अगर कंपनी संचालक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट एक तरफ फैसला सुना सकती है जबकि इसी संदर्भ में जिला कलेक्टर को मिले सम्मन की तामील होने के कारण उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया है।

■ आलापुर गांव में चल रही कंपनी के संचालक को 28 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया

जोन में है, यहा पानी की हमेशा से समस्या बनी हुई है। वहीं खसरा नम्बर 1128-613 और खसरा संख्या 1130-614 की जमीन पर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की एक्वाफील्स टैड्स प्रा. लि. ने पानी फिल्टर करने की कंपनी लगा दी जिसका वहां के ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन उनके विरोध पर जिला प्रशासन ने कोई सजा नहीं लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वे दो बार जिला कलेक्टर से भी इस विषय पर मिले कि अगर यह कंपनी यहां बनी तो हमारा सारा पानी सूख लेगी, लेकिन ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र पर जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की, आखिर में ग्रामीणों ने अदालत की शरण ली।

जसवंत सिंह वगैरह ने सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 की अदालत में दायर की वाद पर न्यायालय ने एक्वाफील्स कंपनी और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किए हैं। समाजसेवी जसवंत यादव ने बताया है कि अलापुर डार्क जोन में आता है यहां पीने के पानी तक की समस्या है। ऐसे में इस कंपनी के लग जाने से कृषि प्रभावित हो रही है क्योंकि यहां लगे दर्जनों पंप रोजाना जमीन से जल का दोहन कर रहे हैं जिससे हमारे खेतों में लगे पंपों का पानी सूखने लगा है, अगर समय रहते सरकार ने इस पर कार्यवाही नहीं की तो ग्रामीणों को यहां से पलायन करना पड़ सकता है।

हथियार के साथ दो गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर रिजर्व पुलिस लाइन का हैड कांस्टेबल और जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ पंचायत समिति का एलडीसी अवैध हथियार के साथ पकड़े गए हैं। पुलिस नाकाबंदी में इनके पास से 12 बोर गन और कारतूस मिले हैं। फिलहाल पुलिस अब इनसे पूछताछ में जुटी है। ड्राइंगवांस पुलिस इनसे पड़ताल कर रही है। आर्म एक्ट

में केस बनाया गया है। थानाधिकारी दीलाराम ने बताया कि बुधवार को पुलिस थाने के सामने नाकाबंदी की गई थी। तब एक गाड़ी में सवार दो लोगों को पकड़ा गया। इनके पास में 12 बोर गन और कारतूस मिले। जिस पर पूछताछ में पता लगा कि एक व्यक्ति जैसलमेर के सांगड़ स्थित प्लासट देवी कोट का अमीन खां पुत्र

रामजान खां है, जोकि रिजर्व पुलिस लाइन में हैड कांस्टेबल के पद कार्यरत है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने खुद को जैसलमेर के नाचना निवासी और हाल मोहनगढ़ पंचायत समिति का एलडीसी होने बताया है। यह लोग हथियार लेकर किस तरफ जा रहे थे, इस बारे पता लगाया जा रहा है। गन और कारतूस के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

तस्करी में वांटेड 25 हजार इनामी अपराधी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट जिला पश्चिम में ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में गुरुवार को डीएसटी वेस्ट में जीआरपी थाने में वांटेड 25 हजार के इनामी आरोपी को पकड़ा है। वह पांच साल से मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में राजकीय रेलवे पुलिस का वांटेड था। उसे अब जीआरपी को सौंपा गया है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम कमल शेखावत ने बताया कि जिला पश्चिम की तरफ से ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जिला पश्चिम की डीएसटी प्रभारी एसआई महेंद्र सिंह

प्रतिबंध के बावजूद राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए

उदयपुर, (कासं)। नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने के कारण सूरजपोल थाना एवं भूपालपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि उदयपुर शहर में किसी भी सार्वजनिक राजकीय संपत्ति पर बैनर एवं पोस्टर नहीं चिपकाने हेतु कई बार अपील के साथ सख्त कार्रवाई भी की गई है, लेकिन निगम द्वारा की

गई अपील को नजरअंदाज करते हुए फिर से सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए गए, जिससे शहर की खूबसूरती बिगड़ रही है। शहर के दुर्गा नर्सरी, टी आर आई तिराहा, कुम्हारों का भट्टा पुलिया के नीचे, फतह स्कूल दीवार, सूरजपोल के पास स्मार्ट कंप्यूटर अनंदा प्लाजा द्वारा पोस्टर चिपकाये हुए थे। इसको लेकर पोस्टर चप्सा करने वाले के खिलाफ शहर के दो थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

शादी का झांसा देकर पांच लाख की ठगी

हनुमानगढ़, (निसं)। भादरा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर ठगी का एक मामला सामने आया है। एक युवक से विवाह के नाम पर लगभग पांच लाख रुपए नकद और सोने-चांदी के जेवर हड़प लिए गए। बाद में महिला घर से नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। पुलिस ने महिला सहित तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को रासलाना निवासी वीर सिंह ने शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में जयवीर और उसके पिता बलवंत सहू, जो नुवा, गोगामेड़ी के निवासी हैं, ने उनकी शादी कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने भादरा निवासी स्वाती नामक युवती से विवाह कराने के लिए खर्च और 3 लाख

रुपए की शर्त रखी। आरोपियों ने रिश्तेदारी का हवाला देकर वीर सिंह का भरोसा जीता, जिस पर वह सहमत हो गए। शिकायत के मुताबिक, 26 जनवरी 2025 को आरोपी जयवीर और बलवंत एक युवती को लेकर रासलाना पहुंचे। परिवारजनों की मौजूदगी में स्वाती का विवाह वीर सिंह से करा दिया गया। विवाह के बाद वीर सिंह ने स्वाती को सोने की चेन, चांदी की बिछिया और पायजेब दी। इसके अलावा 50 हजार रुपए खर्च के तौर पर और लगभग 2 लाख रुपए बिचौलिया शुल्क के रूप में आरोपियों को दिए गए।

पीड़ित वीर सिंह के अनुसार, शादी के बाद स्वाती उसकी पत्नी के रूप में रहने लगी और घर-परिवार संभालने का भरोसा दिलाया। हालांकि, 22 मार्च

2026 को जब परिवार के लोग खेत में काम करने गए हुए थे, तब घर पर केवल वीर सिंह की बुजुर्ग मां और स्वाती मौजूद थी। वीर सिंह ने आरोप लगाया कि इसी दौरान स्वाती उसकी मां के पास रखे लगभग 10 तोला सोने के जेवर और 2 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गई। जब वीर सिंह ने जयवीर और बलवंत से संपर्क किया, तो उन्होंने धमकी दी कि यदि कोई कानूनी कार्रवाई की गई तो उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। इसके बाद पीड़ित वीर सिंह ने भादरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। भादरा पुलिस ने परिवारी वीर सिंह को शिकायत पर जयवीर, बलवंत और स्वाती के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच एसआई राजेंद्र सिंह को सौंपी गई है।

मुंहबोली बहन से दुष्कर्म, दस दिन तक बंधक बनाया

श्रीगंगानगर, (निसं)। महिला को काम के बहाने श्रीगंगानगर लेकर जाकर रेप करने का मामला सामने आया है। महिला को 10 दिन तक बंधक बनाकर भी रखा। महिला ने कहा कि आरोपी उसे मुंहबोली बहन कहता था और इसी का फायदा उठाकर उसे अपने साथ ले गया। आरोपी ने उसका फोन तोड़ दिया, जिसके कारण उसकी किसी से बात नहीं हो पाई। किसी तरह उसके हाथ आरोपी युवक का फोन लगा, तो उसने अपने पति को कॉल कर आपबीती बताई। इसके बाद पति, देवर और ससुर उसे लेने के लिए राजस्थान पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही आरोपी श्रीगंगानगर में महिला को छोड़कर भाग गया। इसके बाद उसे यहां लाकर अस्पताल में मेडिकल के लिए

दाखिल करवाया। वहीं पति ने कहा कि उसने पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब फिर से उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एक गांव की रहने वाली 23 वर्षीय महिला अपने पति के साथ गांव में मजदूरी करती है और उसका एक बेटा भी है। महिला के अनुसार, गांव का ही मंगल सिंह नाम का युवक, जो किन्नू के बागों में काम करता है और उसे बहन कहता था, 23 मार्च को उसे मजदूरी के बहाने अपने साथ ले गया।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी उसे श्रीगंगानगर, जयपुर, बीकानेर और हरिद्वार ले गया। बाद में वह उसे वापस श्रीगंगानगर में अपने दोस्त प्रवीण के घर

छोड़ गया। इस दौरान आरोपी ने लगातार उसके साथ मारपीट की और रेप किया। करीब 10 दिन तक बंधक बना कर रखा। महिला ने आरोप लगाया कि जाते समय आरोपी उसकी सोने की बाली और पायल भी अपने साथ ले गया और उसका फोन तोड़ दिया, ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके। करीब एक सप्ताह बाद आरोपी उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया। थाना खुशियां के प्रभारी रणजीत इंस्पेक्टर परमिला और गुरदीप सिंह को सौंप दी गई है। पुलिस ने आरोपी मंगल सिंह के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।

महिला सुरक्षा, सायबर अपराध और नशे पर लगाम लगाने पर हमारा फोकस है : डीजीपी

बीकानेर, (निसं)। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने गुरुवार को अपने दो दिवसीय दौर में अनेक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी निभाई। उन्होंने अश्व बल शाखा, सीसीटीएनएस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस लाइन का निरीक्षण किया

■ पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने बीकानेर में पुलिस लाइन में मैस व मोटर शाखा का निरीक्षण किया

■ पुलिस कार्मिकों के दफ्तर या थाने में व्यवहार को लेकर शिकायत आना बहुत गंभीर है : डीजीपी राजीव शर्मा



डीजीपी राजीव शर्मा ने मैस में जवानों को मिलकर डाइट के बारे में पूछा।

और सभी कक्षाओं और संचायित दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के साथ एडीजी क्राइम विपिन पांडे, आईजी ओमप्रकाश, डीआईजी कुंवर राष्द्रीय, एसपी मृदुल कच्छवा सहित अनेक पुलिस अधिकारी थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कक्षाओं, रिपोर्टिंग और व्यवस्थाओं की गहन जांच की तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। डीजीपी ने पुलिस लाइन मैस और मोटर शाखा का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मैस में जवानों को मिलने वाली डाइट के बारे में पूछा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके

अलावा बाहनों की उपलब्धता और आवश्यकताओं को लेकर भी जानकारी ली। इस अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर का भी उद्घाटन किया गया।

मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कहा कि पुलिस कार्मिकों के दफ्तर या थाने में व्यवहार को लेकर शिकायत आना बहुत गंभीर है। गलत व्यवहार जनता के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान को पुलिसिंग में मॉडल स्टेट बनाना है। थाना पुलिसिंग की पहली इकाई है। थाने नागरिकों के अनुकूल हों। नागरिक, गरिमा और न्याय पहले थानों का आदर्श वाक्य होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं

और बच्चियों की सुरक्षा पर फोकस किया जाएगा। इसके लिये स्कूल स्तर पर महिला सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज के बदलते दौर में तकनीक पुलिस की मजबूत साथी होगी। आधुनिक निगरानी प्रणाली को और प्रभावी करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस सेवा को बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास होगा। डीजीपी ने शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में जवानों की पदोन्नति के मामले में मेंडिंग चल रहे थे। उन जिलों के अधिकारियों को जल्द पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश दिए। साथ ही पेंडेंसी कम करने के

आदेश दिए। डीजीपी राजीव शर्मा ने राजस्थान पुलिस के हाल ही में किए डिवाय ऑपरेशन पर कहा कि हर गलत चीज के प्रति हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध और नशे पर लगाम लगाना हमारा सीधा फोकस है। बीकानेर सीमावर्ती इलाका होने के कारण सतर्कता अधिक बरती जाएगी। राज्य सरकार का भी यही ध्येय है कि आम को लगातार ट्रेनिंग करने की आवश्यकता होती है। डीजीपी राजीव शर्मा ने बीकानेर प्रवास के दौरान संपर्क सभा में सौधियों को बताया है कि आम आदमी के साथ हमारा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए।

युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिये एसआईसीसी की स्थापना होगी

जयपुर। राज्य सरकार के कौशल, नियोजन एवं उद्यमता विभाग द्वारा युवाओं को वैश्विक रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। यह पहल भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अंतरराष्ट्रीय माजारों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें वैश्विक जांब मार्केट के लिए सक्षम बनाना है।



भरतपुर कलेक्टर ने मौका मुआयना कर कुम्हरे में दो उपयुक्त स्थलों का चयन किया।

जयपुर में उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग, मेडिकल, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान/आईटीआई तथा आईटी एवं मैनेजमेंट संस्थानों की उपलब्धता के साथ-साथ प्रशिक्षित एवं शिक्षित युवाओं की बड़ी संख्या मौजूद है, जो वैश्विक रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर में एसआईसीसी की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होगा। इस हेतु जयपुर स्थित महात्मा गांधी शासन एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान (जेएलएनएम) की उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा 16 मार्च को प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया जा

किये जाने का संकेत दिया है। इस हेतु भरतपुर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी द्वारा दो अप्रैल को मौका मुआयना कर कुम्हरे में दो उपयुक्त स्थलों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है तथा केंद्र सरकार के अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत यह केंद्र मई 2026 तक प्रारम्भ होने की संभावना है।

माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राज्य के 17 लाख युवाओं का पंजीयन- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म के तहत प्रदेश में चल रही गतिविधियों की समीक्षा की

जयपुर, 2 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने में युवा शक्ति की भूमिका सबसे अहम है। प्रधानमंत्री की मंशा है कि युवाओं की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग किया जाए। "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" देश की इसी युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने का सशक्त माध्यम बन रहा है।

उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में 17 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार युवाओं को कोशल विकास, रोजगार से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को अवसर देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" के तहत प्रदेश में हो रही गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं में नये की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिये नशा-मुक्ति की दिशा में भी गतिविधियाँ संचालित की जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नशा मुक्ति, फिटनेस और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" के तहत प्रदेश में हो रही गतिविधियों की समीक्षा की।

"फिट राजस्थान, हिट राजस्थान" के विजन को हर गांव और शहर तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में पेरपलीक और भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं से युवाओं के सपनों पर कुटाराघात हुआ। अब भर्ती परीक्षाएँ पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध रूप से आयोजित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरी

के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख से ज्यादा पदों का भर्ती केलिए जारी किया जा चुका है।

बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि "माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म" युवाओं को सरकार से सीधे जोड़ने का सशक्त डिजिटल

माध्यम है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत युवा कनेक्ट, विकसित भारत पद यात्राएँ, नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यंग प्रोफेशनल राउंडटेबल और माय भारत बजट क्वेस्ट जैसे विभिन्न कैम्पेन और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से युवा अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं, जिससे विकसित

अदालती आदेश के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आयोग अपने आप ही चुनाव के कार्यक्रम को 15 तारीख से आगे बढ़ाने का फैसला कैसे ले सकता है, जबकि इस संदर्भ में न तो अदालत में कोई आवेदन पेश किया गया है और न ही अदालत ने कोई अनुमति दी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाअधिवक्ता को भी अदालत में उपस्थित होने का आग्रह किया। महाअधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार कुछ ही दिनों में चुनाव के कार्यक्रम को 15 अप्रैल से आगे बढ़ाने के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत करने जा रही थी। परंतु आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम कैसे और किस प्रकार से तय

किया जा रहा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार व चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के संदर्भ में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में अदालत के समक्ष ऐसा कोई भी आवेदन पेश नहीं किया गया है। अदालत ने आगे कहा कि प्रदेश के चुनाव आयोग को इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि उन्होंने चुनाव स्वतः ही आगे कैसे बढ़ाया, जबकि अदालती आदेश इसके बिल्कुल विपरीत थे। इसके साथ ही, अदालत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी करा है।

मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े ब्रिज पर अमेरिका का हमला

तेहरान, 02 अप्रैल। ईरान की राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर कराज से जोड़ने वाले एक 'बी1' हाईवे ब्रिज' पर गुरुवार को हवाई हमला किया गया। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं और आसपास के इलाकों में भी नुकसान हुआ है।

यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। करीब 1050 मीटर लंबा और

3800 करोड़ रु. की लागत से बना यह पुल तेहरान को ईरान के उत्तरी भाग से जोड़ता है।

136 मीटर ऊंचे पिलर वाला यह प्रोजेक्ट करीब 400 मिलियन डॉलर में बना था।

इस कूटनीतिक पहल का समर्थन करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय आस सहमित और दृढ़ संकल्प का समर्थन मिलना चाहिए। शर्मा का यह बयान अमेरिका-इजरायल तथा ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के रूख से अलग है।

यह पुल ईरान बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, इसलिए इसके नुकसान से ट्रेडिंक और व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस इस युद्ध के दौरान

केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण में बताया कि भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत युवा कनेक्ट, विकसित भारत पद यात्राएँ, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यंग प्रोफेशनल राउंडटेबल और माय भारत बजट क्वेस्ट जैसे विभिन्न कैम्पेन व कार्यक्रम इस प्लेटफॉर्म पर आयोजित होते हैं।

भारत के विजन को गति मिली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश से बने विकसित भारत यंग लीडर्स से संवाद भी किया। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारीगण एवं यंग लीडर्स उपस्थित थे।

पश्चिम एशिया संकट पर कांग्रेस के आनंद शर्मा ने भारत की कूटनीति को सराहा

इससे पहले शशि थरूर भी भारतीय नीति की सराहना कर चुके हैं

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। शशि थरूर के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने पश्चिम एशिया के ताजा संकट में भारत की कूटनीति को परिपक्व और कुशल बताते हुए कहा है कि इसने संभावित खतरों से सफलतापूर्वक बचाव किया है।

इस कूटनीतिक पहल का समर्थन करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय आस सहमित और दृढ़ संकल्प का समर्थन मिलना चाहिए। शर्मा का यह बयान अमेरिका-इजरायल तथा ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के रूख से अलग है।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस इस युद्ध के दौरान

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। केन्द्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच, पेट्रोकेमिकल उत्पादों का मुख्य रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इसके तहत केन्द्र सरकार ने 40 प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों से अगले तीन महीने तक के लिए पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की है। केन्द्र सरकार के इस कदम का उद्देश्य कच्चे माल की कीमत में होने वाली बेतहाशा वृद्धि से भारतीय मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को सुरक्षित रखना है।

अमेरिका-इजरायल तथा ईरान के बीच जारी जंग के दौरान केन्द्रसरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से फार्मास्यूटिकल, ऑटो कॉम्पोनेंट्स, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पैकेजिंग और केमिकल मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे उद्योगों को काफी फायदा होगा। कस्टम ड्यूटी हटाने से इन उद्योगों की उत्पादन लागत में गिरावट आएगी और आम आदमी को महंगाई के बोझ से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी।

इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में एसिटिक एसिड, एपॉक्सी रेंजिन, यूरीफाइंड टैरिफॉलिक एसिड, मेथेनॉल, फिनोल, टॉल्युन,

इन उत्पादों में एसिटिक एसिड, एपॉक्सी रेंजिन, मेथेनॉल, अमोनिया, एथिलिन पॉलिमर्स आदि शामिल हैं।

एनहाइड्रस अमोनिया, एथिलीन पॉलीमर्स और कई तरह के फॉर्मल्हाइडहाइड पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 30 जून तक के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने इन अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों के इंपोर्ट से कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला ऐसे समय में लिया है, जब पश्चिमी एशिया में जियो-पॉलिटिकल टेंशन चरम पर पहुंचा हुआ है। इस टेंशन का असर दुनिया भर में अहम पेट्रोकेमिकल कच्चे माल की उपलब्धता पर पड़ना शुरू हो गया है। अमेरिका और इजरायल तथा ईरान के बीच चल रही लड़ाई के चलते वैश्विक स्प्लाइ चैन को भी झटका लगा है, जिसकी वजह से इन उत्पादों की कीमत में भी तेजी आने लगी है। ऐसे में कस्टम ड्यूटी हटा कर केन्द्र सरकार भारतीय उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की लगातार स्प्लाय सुनिश्चित करना

चाहती है। इस संबंध में बताया गया है कि कस्टम ड्यूटी में इस झटके का उद्देश्य स्प्लाय को बनाए रखने और वैल्यू चैन में कीमतों में बड़ी तेजी को रोकना है। इस कदम से केन्द्र सरकार को यह उम्मीद थी है कि एंड कंज्यूमर्स के लिए कीमतों में स्थिरता आएगी, क्वांटि कच्चे माल की लागत में कमी से कंपनियों को उपभोक्ताओं पर बढ़ाई हुई कीमतों का दबाव नहीं डालना पड़ेगा।

आईपैक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

काम देख रही है। आईपैक से पहले प्रशांत किशोर भी जुड़े रहे हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिला है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार संभाल रही आई पैक नई दिल्ली, बंगलुरु और हैदराबाद के ऑफिस में छापेमारी की। बंगलुरु में आईपैक के डायरेक्ट ऋषिकांत सिंह के आवास पर भी रेड हुई। ईडी सूत्रों के मुताबिक, कोयला तस्करी मामले की जांच के लिए आई पैक के ठिकानों को खंगाला गया है।

आईआरजीसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के दौरान हुई। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिगेडियर जनरल फतह अलीजादेह की जान दुश्मनों के हवाई हमले में गई है।

मोहम्मद अली फतह अलीजादेह कोई साधारण फौजी नहीं थे। वे आईआरजीसी की उस स्पेशल वॉलंटियर यूनिट की कमान संभाल रहे थे, जो गुरिल्ला युद्ध और बेहद कठिन ऑपरेशंस

को अंजाम देने के लिए जानी जाती है। इस यूनिट को सीधे तौर पर फतेहिन कहा जाता है। सीरिया पर गुरुयुद्ध में राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार को बचाने और आतंकियों से लोहा लेने के लिए एफडी फतेहिन यूनिट को मैदान में उतारा गया था। फतह अलीजादेह जैसे अनुभवी कमांडर का मारा जाना ईरानी के लिए बड़ा क्षित है।

होर्मुज़ स्ट्रेट पर ब्रिटेन में 60 देशों की मीटिंग

भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिसरी ने किया

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की पहल पर करीब 60 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों ने ऑनलाइन तरीके से होर्मुज़ संकट पर गुरुवार को चर्चा की। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिसरी ने किया और अध्यक्षता ब्रिटेन के विदेश मंत्री यवेत कूपर ने की। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ईरान की ओर से होर्मुज़ स्ट्रेट की आंशिक नाकाबंदी के मद्देनजर सुरक्षित समुद्री परिवहन सुनिश्चित करना था।

मिसरी ने चर्चालू माध्यम से चर्चा में भाग लेते हुए क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन मार्गों की सुरक्षा पर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने दुनियाभर के देशों के

■ भारत ने मीटिंग में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत इकलौता देश है जिसने अपने जांबाज नाविकों को खोया है।

सामने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही हर देश का हक है। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। विदेश सचिव ने इचिंता जताई कि इस पूरे संकट का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है।

ब्रिटेन की ओर से बुलाई गई बैठक में भारत ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों में भारत इकलौता ऐसा देश है, जिसने

अपने जांबाज नाविकों को खोया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल और अधिक युद्ध नहीं है। अगर दुनिया को इस संकट से बाहर निकलना है, तो सभी पक्षों को तुरंत हथियारों को शांत कर बातचीत की मेज पर लौटना होगा।

वहीं, बैठक के बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा, होर्मुज़ से जहाजरानी सेवाओं को फिर से शुरू करना आसान नहीं होगा और इसके लिए समुद्री उद्योग साझेदारी के अलावा, सैन्य शक्ति और राजनयिक

गतिविधियों का एक संयुक्त मोर्चा आवश्यक होगा। स्टार्मर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की उस अपनी को स्पष्ट नकार चुके हैं कि ब्रिटेन व यूरोप के अन्य देशों को होर्मुज़ खुलवाने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहिए।

इस बीच, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चेतावनी दी कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य को आवागमन का मुद्दा ईरान युद्ध का ही परिणाम है और जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जलडमरूमध्य स्थिर नहीं रहेगा। वांग यी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने शीघ्र युद्धविराम का भी आन किया।

ऑस्ट्रिया ने भी अमेरिका को एयरस्पेस देने से इन्कार किया

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। ईरान और यूएस-इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि, कई देश युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे समय में अमेरिका को झटका लगा है। अब ऑस्ट्रिया ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रिया ने अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है।

ऑस्ट्रिया ने ईरान से जुड़े सैन्य ऑपरेशनों के लिए अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की अमेरिकी मांग टुकारा दी है। ऑस्ट्रिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला देश के सख्त तटस्थता कानून के तहत लिया गया है।

ट्रंप ने अमेरिकी जनता से कहा, हम जीत गए हैं

अमेरिका की जनता को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ईरान को नष्ट करने का दावा किया

वॉशिंगटन, 02 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध पर देश को संबोधित किया है। भारतीय समयानुसार, गुरुवार सुबह साढ़े छह बजे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान सफल रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज ने बहुत कामयाबी के साथ ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म करते हुए उनकी परमाणु हथियार हासिल करने की उम्मीद को खत्म किया है। उन्होंने ईरान में अमेरिका के लक्ष्य पूरे होने का ऐलान

■ ट्रंप ने कहा कि ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल खत्म हो रहा है।

किया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सेना ने ऑपरेशन एफिक फ्यूरी के तहत युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और जबरदस्त

जीत हासिल की है। यह एक ऐसी जीत है, जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखी होगी। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके ज्यादातर नेता अब मारे जा चुके हैं। डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है। उनकी हथियारों की फैक्टरियां तथा रॉकेट लॉन्चर टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे हैं। अब उम्में से बहुत ही कम बचे रह गए हैं।

सात जजों को नौ घंटे बंधक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के एक समूह ने न्यायिक अधिकारियों के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, जो एसआईआर से संबंधित जरूरी कार्य कर रहे थे।

सुप्रिम कोर्ट ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हर चीज "राजनीतिक" हो चुकी है, जिसके कारण प्रशासन पर से लोगों का विश्वास पूरी तरह उठ गया है। सवाल यह है कि राज्य में बढ़ती अराजकता और हमलों के बावजूद केन्द्र सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है।

निकृष्ट किस्म की हिंसा की इन घटनाओं के बावजूद, आरोप है कि ममता बनर्जी खुले मंचों से और उकसाने वाले बयान दे रही हैं। उन्होंने कांग्रेस, ओवैसी, माकपा तथा भाजपा पर इन घटनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है।

बताया गया कि उन्होंने लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, से अपील की कि जो भी उनके पास उपलब्ध हो, उसके साथ बाहर निकलें और एसआईआर

कार्य को रोकें। उन्होंने यह भी कहा कि "हमारी माताएं और बहनें चुप क्यों हैं?" और वादा किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम नहीं होने दिया जाएगा।

ममता बनर्जी हर कदम पर गैर-जिम्मेदारी और उकसावे की राजनीति को बढ़ाती रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि अगर वे नहीं होतीं, तो बंगाल में बहुसंख्यक समुदाय (हिंदू) जीवित नहीं रहता। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनके बिना, यह समुदाय दूसरे समुदाय के हमलों का शिकार हो सकता है।

इसके बाद से वे किसी भी कीमत पर एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण) कार्य को रोकने के लिए संगठित प्रयास करती नजर आई हैं। राज्य के शीर्ष राजनीतिक स्तर से दिए गए ऐसे बयानों के बाद लोगों में टकराव का माहौल बन गया है।

चार न्यायिक अधिकारी एसआईआर के तहत मतदाता सूची सुधार का काम कर रहे थे। इन

अधिकारियों को भीड़ ने उनके कार्यालय में घेरेकर रोक लिया, जो कथित तौर पर ममता बनर्जी के आन के अंशरूप ही हुआ।

इन न्यायिक अधिकारियों ने पहले ही राज्य प्रशासन और कलकत्ता उच्च न्यायालय को उस क्षेत्र में अपनी असुरक्षा के बारे में सूचित किया था, जहां वे कार्य कर रहे थे। उन्होंने अपने कार्यस्थल को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन उनकी मांग को राज्य प्रशासन तक ठीक से पहुंचाया ही नहीं गया।

सुप्रिम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं राज्य प्रशासन को सुरक्षा देने में विफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल उठाया कि यदि न्यायिक अधिकारियों को ही सुरक्षा नहीं दी जा सकती, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं।

पूरा कार्य कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत किया जा रहा है।

आप ने राघव चड्ढा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोकसभा के 128 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, तब पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा ने उनका कहना था कि बच्चे के जन्म पर से इनकार कर दिया था।

सूत्रों का कहना है कि कई मौकों पर चड्ढा सदन में बने रहे, जबकि आप सहित, विपक्ष के अन्य सदस्य वॉकआउट कर गए थे।

वर्ष 2025 के दिल्ली चुनावों में आप की हार के बाद चड्ढा ने पार्टी के भीतर तो लो प्रोफाइल रखा और केवल व्यापक जनहित के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित रखा था।

बताया जाता है कि चड्ढा ने आप संस्थापक अरविन्द केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित शराब घोटाले में बर्त होने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाल ही में केजरीवाल द्वारा भाजपा के खिलाफ संबोधित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभा में भी वे अनुपस्थित रहे। एक सूत्र ने कहा, "वे

अपना अलग एजेंडा चला रहे थे।" हाल ही में चड्ढा ने भारत में पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने की मांग उठाकर सुर्खियां बटोरी थीं। उनका कहना था कि बच्चे के जन्म पर माता-पिता, दोनों को बधाई दी जाती है, लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी मुख्यतः माता पर आ जाती है। उन्होंने कहा कि पालन-पोषण की जिम्मेदारियां समान रूप से साझा होनी चाहिए।

हवाई अड्डों पर महंगे खाने के खिलाफ उनकी पहल के चलते 'उड़ान यात्री कैफे' जैसे किफायती फूड काउंटर शुरू किए गए, जिससे यात्रियों को सस्ता खाना मिल सके। इसे उपभोक्ता अधिकारों की जीत बताया गया है।

सूत्रों के अनुसार, पार्टी के इस फैसले से नाराज चड्ढा भाजपा नेतृत्व के संपर्क में हैं और उनके भगवा दल में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एडवोकेट पीबी सुरेश ने दलील देते हुए कहा कि कहा कि सुप्रिम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह 31 मार्च से पहले प्रार्थियों का मामला तय करे और उनके अधिकारों को संरक्षित रखे।

खंडपीठ ने उनकी अपीलों पर पक्षकारों की बहस सुनकर गत 19 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में भर्ती परीक्षा होने से प्रार्थी पक्ष के अधिकार प्रभावित होंगे। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से ऑपरेशन शिवमंगल शर्मा ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने भर्ती की सभी जरूरी प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली हैं।

'5037 बीघा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मकान तोड़ने की नौबत आ जायेगी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पी सी भंडारी ने कहा कि राज्य सरकार को पूरी तरह से करना हाउसिंग बोर्ड को अपनी जमीन बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिये और इसी में राज्य सरकार का ओर आम जनता काहित है। उन्होंने कहा कि 5037 बीघा जमीन में से वह जमीन, जिस पर अतिक्रमण नहीं है, उसे बचाने का प्रयास राज्य सरकार को पूरी तरह से प्रार्थी पक्ष के अधिकार प्रभावित होंगे। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से ऑपरेशन शिवमंगल शर्मा ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने भर्ती की सभी जरूरी प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में इस स्तर पर भर्ती परीक्षा स्थगित करने से अव्यवस्था पैदा होगी। इसलिए भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं की जाए।

रोका जा सके। अदालत ने इस दस्तावेज को बनाने व अदालत में पेश करने के लिये एसजी व याचिकाकर्ता को समय दिया है और इस मामले की अगली तारीख 1 मई, 2026 तय की है।

वृद्धा से 80 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपराध है। जिसमें कई स्तरों पर करीब ढाई दर्जन से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया है।

जमानत याचिका में कहा गया था कि उसके खाते में पांच लाख रुपए आए थे और वह पीडिता को दस लाख रुपए देकर राजीनामा कर रहा है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। वहीं अदालत में पेश होकर पीडित महिला ने कहा था कि उसे जांच एजेंसी के बयान नहीं दिला पा रही है और वह दबाव में राजीनामा कर रही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने अगले 27 मार्च को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।